



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2004/फाल्गुन 26, 1925

No. 65 ]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2004/PHALGUNA 26, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग संबंधालय

(वाणिज्य विभाग)

(काउन्सली एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2004

अधिसूचना आद्य परिणाम

**विषय :** चीन जनवादी गणराज्य मूल के अधक वहाँ से नियातित टाइटेनियम डाइआक्साइड के आयतों के संबंध में पाटनरोधी जाँच।

सं. 14/51/2002-डॉजीएडी.—भारत सरकार 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाइट वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) विषय, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

1.0 जाँच के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत घरेलू उद्योग की ओर से टाइटेनियम डाइआक्साइड मैन्युफॉर्मर्स एसोसिएशन (इसके बाद इसे याचिकाकर्ता कहा गया है) की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से नियातित टाइटेनियम डाइआक्साइड (जिसे इसके बाद सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा फाइल किये गये आवेदन की प्रारम्भिक जाँच पड़ताल में कुछ कमियाँ पार्या गयी जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा बाद में दूर कर दिया गया। इसलिए याचिका को विधिवत प्रलेखित मान लिया गया।

(iii) प्राधिकारी ने उक्त नियम-5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच की कार्रवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये पाटन आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में सम्बद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

(iv) प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची के शीर्ष 28.23.00 और 28.23.00.01 के अन्तर्गत वर्गीकृत वहाँ के मूल के अथवा चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित टाइटेनियम डाइआक्साइड के आयातों से सम्बन्धित पाटन रोधी कार्रवाई शुरू करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे 16 जनवरी, 2003 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

(v) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों (जिनका विवरण याचिकाकर्ता ने उपलब्ध कराया) आयातकों (जिनका विवरण याचिकाकर्ता ने उपलब्ध कराया), वाणिज्य मंडल तथा शिकायतकर्ताओं को उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से भी अवगत कराने का मौका दिया।

(vi) उपरोक्त नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार प्राधिकारी ने याचिका की एक प्रति सभी सात निर्यातकों और भारत में सम्बद्ध देश के दूतावास को भेजी। अगोपनीय चायिका की एक प्रति भी अनुरोध पर अन्य हितंबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गयी।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को संगत सूचना मँगाने के लिए प्रश्नावली भेजी। प्रारम्भिक जाँच परिणामों के पूर्व निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना प्रस्तुत किया गया था:-

1. मै0 गोऑग्सी दहुआ केमिकल फैक्ट्री, चीन;
2. मै0 गोऑग्सी जिंग में जियांग टाइटेनियम डाइआक्साइड कं0लि0, चीन;
3. मै0 गोऑग काँग वू टाइटेनियम मैन्युफैचरिंग कं0लि0, चीन;
4. मै0 शौगान केमिकल प्लान्ट, चीन;

(viii) नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास को भी नियम 6(2) के अनुसार इस अनुरोध के साथ जाँच शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था कि अपने देश के सभी सम्बन्धित निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजें। जात निर्यातकों को भेजे गये पत्र, याचिका, और प्रश्नावली की एक प्रति, नियम 6(3) के अनुसार सम्बद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गयी।

(ix) नियम 6(4) के अनुसार सम्बद्ध माल के सभी जात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गयी थी। निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना दी गयी थी:-

1. मै0 स्नोसेम इण्डिया लि0, मुम्बई;
2. मै0 भीमराजका इस्पेक्स लि0, मुम्बई;
3. मै0 केमी0 इन्टरप्राइजेज, मुम्बई;
4. मै0 नेरोलैक पेन्ट;
5. मै0 बर्जर पेन्ट;
6. ईस्टकार्प इन्टरनेशनल, कोलकाता

निर्यातकों / आयातकों ने प्रश्नावली का उत्तर भेजने के लिए अतिरिक्त समय माँगा था। प्राधिकारी ने अनुरोध पर विचार करते हुए हितबद्ध प्रक्षकारों द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों की समयावधि को बढ़ाकर दो सप्ताह करने की अनुमति दी।

(x) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार उसके द्वारा सार्वजनिक फाईल के रूप में रखे गए अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अंगोपनीय अंश उपलब्ध कराये और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उसे खुला रखा।

(XI) प्राधिकारी ने 6 जून 2003 की अधिसूचना द्वारा प्रारम्भिक जाँच परिणाम अधिसूचित किये और हितबद्ध पार्टियों से अनुरोध किया कि वे इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत करायें।

(XII) प्राधिकारी ने 8 अगस्त, 03 को मौखिक सुनवाई की। जो हितबद्ध पक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए थे उनसे अनुसूची के अनुसार अपने लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था।

(XIII) \*\*\* यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गयी सूचना का घोतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

(XIV) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से सूचना माँगी और उसके द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन किया तथा इस प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता के टी.टी.पी.एल., केरल और समर्थक मै0 कोलमैक केमिकल्स कोलकाता के परिसरों की जाँच की गयी थी।

(XV) प्राधिकारी ने लागत जाँच भी की और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं भारत में सम्बद्ध वस्तु की इटतम उत्पादन लागत तथा उसको बनाने और बेचने की लागत का आकलन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी.ए.ए.पी.) के आधार पर किया।

(XVI) जाँच 01 जनवरी 2002 से 31 दिसम्बर 2002 तक की अवधि अर्थात् जाँच अवधि के लिए की गयी थी।

(XVII) याचिकाकर्ता से क्षति के बारे में अतिरिक्त ब्लौरे माँग गये थे जिन्हें प्रस्तुत कर दिया गया था।

(XVIII) प्राधिकारी ने उचित समझी गयी सीमा तक घरेलू उद्योग एवं सहयोगी निर्यातकों का मौके पर सत्यापन किया।

(XIX) केन्द्र सरकार ने जाँच पूरी करने के लिए 09.01.2004 के कानूनों 354/51/2003-टीआरयू के तहत 16.01.2004 से दो माह की समय वृद्धि प्रदान की।

(XX) उपरोक्त नियमों के नियम-16 के अनुसार इन जाँच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टीयों को किया जा रहा है और इन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अन्तिम जाँच परिणामों में विधिवत् विचार किया जायेगा।

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टीयों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा जाँच:-

## 2.0 घरेलू उद्योग के विचार

(क) उन्हेंने बताया है कि यद्यपि चीन से सम्बद्ध वस्तु के अनेक निर्यातक हैं तथापि केवल कुछ ही निर्यातकों ने लिखित अनुरोध दायर किये हैं। मौखिक सुनवाई में अन्य निर्यातकों अथवा उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति से इस जाँच में इन निर्यातकों की रुचि का अभाव दिखता है।

(ख) उन्हेंने बताया है कि प्रारम्भिक जाँच परिणामों में मै0 दौहा के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की अस्वीकृति के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी का निर्णय कानूनी उपबन्धों के अनुसार है।

(ग) याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्यातक को प्रत्युत्तर के अगोपनीय अंश में पर्याप्त सूचना उपलब्ध करनी चाहिए।

(घ) याचिकाकर्ताओं ने इस बात को दुहराया है कि चीन से हुए आयातों से भारतीय बाजार में याचिकाकर्ता कंपनी की कीमत में वस्तुतः कटौती हो गयी है। जिससे ये पता चलता है कि जाँच अवधि में आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी।

(ङ) याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि चीन ने उक्त सामग्री के रुटायल और ऐनाटेस दोनों ग्रेडों का निर्यात किया है। आयातों की सूचना वर्गीकरण “2823” सहित अनेक सीमा शुल्क वर्गीकरणों में दी गयी है। ये आयात ऐनाटेस श्रेणी में शामिल और सूचित किये गये प्रतीत होते हैं जैसे कि डी.जी.सी.आई.एंड एस. के ऑफिस में यह मानते हुए सूचना दी गयी है कि आठ अंकीय वर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित करने के लिए गौण स्रोत के अनुसार आयातों की विस्तृत सौदेवार सूची उपलब्ध करायी है कि सीमा शुल्क शीर्ष 32.06 के तहत काफी

अधिक मात्रा की सूचना दी जा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त आई.वी.आई.एस ऑकड़ों के अनुसार इन आई.वी.आई.ए.ए.ऑकड़ों में चीन से आयातों की पर्याप्त मात्रा की सूचना सीमा शुल्क शीर्ष 32.06 के तहत दी गयी है।

- (च) चीन से हुए आयातों से घेरलू उद्योग की कीमतों में वस्तुतः कटौती हो रही है। निर्यातक का तर्क डी.जी.सी.आई.एंड एस. के अनुसार औसत निर्यात कीमत पर आधारित है जो (क) ऐनाटेस ग्रेड के लिए निर्दिष्ट वर्गीकरण में रुटायल ग्रेड को शामिल किये जाने; (ख) उत्पाद की सूचना सीमा शुल्क वर्गीकरण 32.06 के तहत दिये जाने के कारण गलत है। वस्तुतः औसत आयात कीमत काफी कम थी और आयातों की पहुँच कीमत आयातों की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम थी। इसके अलावा न केवल कीमत कटौती सकारात्मक है अपितु कम कीमत पर बिक्री भी अत्यन्त प्रासंगिक है।
- (छ) सम्बद्ध वस्तु की माँग कम नहीं हुई है। वस्तुस्थिति यह है कि डी.जी.सी.आई.एंड एस. तथा गौण स्रोतों से सूचित किये गये आयात काफी कम दर्शाये गये हैं।

## 2.0 निर्यातक

### 2.1 मै0 गौणजी दौहा केमिकल फैब्रिरी, चीन (दौहा)

- (क) सम्बद्ध वस्तु के उत्पादक एवं निर्यातक मै0 दौहा निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पाठनरोधी जाँच की शुरुआत से ही पूर्णतया सहयोगी रहे हैं।
- (ख) प्रारम्भिक जाँच परिणामों में की गयी सिफारिशों में प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में दौहा के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने प्राधिकारी से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने और प्राधिकारी द्वारा अन्तिम जाँच परिणामों में की गयी सिफारिशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण घेरलू कीमत और लागत के आधार पर करने का अनुरोध किया है तथा निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत की है।

- i मै0 दौहा में विद्यमान बाजारी स्थितियां
- ii बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए कानूनी मानदण्ड
- iii चीन जनवादी गणराज्य के विदेश व्यापार कानून के उद्धरण
- iv वस्तुओं के आयात और निर्यात के बारे में चीन जनवादी गणराज्य के विनियम के उद्धरण

(ग) उन्होंने इस बात को दोहराया है कि टाइटेनियम डाइआक्साइड की उत्पादक और निर्यातक मै0 दौहा बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के आधार पर चीन और विदेश दोनों में वाणिज्यिक सौदे कर रही है।

#### 2.2 मै0 गौंग्झी कांग वू टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (जी.सी.डब्ल्यू.टी)

उन्होंने बताया है कि मै0 कांग वू टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जिस पर वर्ष 1997 से पूर्व राज्य सरकार का नियन्त्रण था, ने 28.07.2003 से अपना नाम बदलकर मै0 कांग वू शुन फेना टाइटेनियम डाइआक्साइड कंपनी लिमिटेड, चीन रख लिया था। नाम परिवर्तन का कारण निजी क्षेत्र में जाना बताया गया है।

#### आयातक/प्रयोक्ता

#### 2.3 मै0 टाइटेनियम डाइआक्साइड एजेन्ट, डीलर्स एंड कन्जुमर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया:

एसोसिएशन ने टाइटेनियम डाइआक्साइड पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का स्वागत किया है। उन्होंने बताया है कि चीन की वस्तुएं न केवल सस्ती हैं बल्कि घटिया क्वालिटी की भी है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारियों को 'एनाटेस' ग्रेड की आड़ में 'रूटायल' ग्रेड के आयातों पर नजर रखनी चाहिए।

#### 2.4 ईस्टकार्प इन्टरनेशनल, कोलकाता:

पी.एच.डी.बैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिल्ली ने 08.09.2003 के अपने पत्र के तहत मै0 ईस्टकार्प इन्टरनेशनल, कोलकाता का एक अभ्यावेदन भेजा है। आयातकों ने बताया है कि सिफारिश की क्र0सं0 3 कालम 7 में उत्पादक के नाम को प्रारम्भिक जाँच परिणाम में गलत दर्शाया गया है। उत्पादक का नाम 'शाओगान केमिकल प्लान्ट कं0लि0' के बजाय 'शाओगान केमिकल प्लान्ट' पढ़ा जाना चाहिए। इस आशय हेतु उन्होंने चीन की अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संवर्द्धन परिषद, चीन अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल की एक प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3.1 घरेलू उद्योग के विचार

क. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

प्रकटीकरण विवरण में बताए गए आयातों की वास्तविक मात्रा याचिकाकर्ता द्वारा अध्याय 28 के अंतर्गत बताई गई मात्रा से कही अधिक है। प्रत्यक्ष रूप से अध्याय 32 के अंतर्गत आयातों की वास्तविक मात्रा उस मात्रा से काफी अधिक है जिसका याचिकाकर्ता द्वारा आकलन किया गया है। यह इस तथ्य के कारण है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना आई बी आई एस (जिसमें केवल कुछ पत्तन शामिल थे) पर आधारित थी जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना डीजीसीआई एंड एस से होने के कारण इसमें काफी अधिक आयात मात्राओं को प्रदर्शित किया गया है।

अध्याय 32 के अंतर्गत काफी अधिक मात्रा में निर्यात किए गए हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण याचिकाकर्ता इस बात पर ध्यान किए बगैर कि वस्तुओं को अध्याय 32 अथवा 28 के अंतर्गत आयात किया गया है, टाइटेनियम डायऑक्साइड ऐनाटेस के भी ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तव में अध्याय 32 के अंतर्गत उल्लेखनीय मात्राओं को आयात किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को डर है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को अध्याय 32 तक नहीं बढ़ाया जाता है तो आयातों को इस उपशीर्ष के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बगैर स्वीकृत किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता यह समझते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों और अब तक के बीच में अध्याय 32 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बगैर विचाराधीन उत्पाद के काफी मात्रा में आयात किए गए हैं। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि इन आयातों को पाटनरोधी शुल्क के अधीन लाया जाएगा, और विचाराधीन उत्पाद पर उस वर्गीकरण पर विचार किए बगैर जिसके अंतर्गत इसको उल्लेख किया गया है, पाटनरोधी शुल्क लागू होगा।

**ख. पाटन के संबंध में:**

क) याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि निर्यातक के दावे ऐसे हैं कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निर्यातक इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है (क) चीनी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां हैं, और (ख) चीन की राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने इस बात को दोहराया है कि ईसी ने चीन की राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को एमईटी इंकार करना जारी रखा है।

(ख) इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया गया है:-

i. रूस के मूल की सिलिकॉन के मामले में ईसी ने निर्यातक को इन निष्कर्षों के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया है कि रूस के निर्यातकों के लिए मुख्य कच्चे माल की कीमतें विश्व बाजार की कीमतों तथा समुदाय उद्योग की क्षय कीमतों के अनुसार थीं।

ii. अल्जीरिया, बेलारूस, लिथुनिया, रूस और उकरेन (जहां प्राकृतिक गैस मुख्य उत्पाद है) से यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के धोलों के मामले में ईसी ने इन निष्कर्षों के आधार पर कि गैस की कीमतों के निर्धारण में राज्य का प्रभाव पड़ा था, निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया है।

iii. रूस से कुछेक लोहे अथवा इस्पात की रोप्स और केबल्स के मामले में ईसी ने इस आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था वाला दर्जा प्रदान नहीं किया कि कतिपय महत्वपूर्ण निविष्टियों के लिए लागत में बाजार मूल्य और वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं हुए जिनके रूसी मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत लेखा मानकों से भिन्न थे।

ग) लेखों के अनुरक्षण तथा लेखा परीक्षण और परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि जब कंपनी राज्य के स्वामित्व वाला एक उद्यम है तो यह भी कैसे दावा किया जा सकता है कि कंपनी की पूँजी राज्य से नहीं आई थी।

घ) प्रत्येक उद्यम द्वारा कर रिटर्नस भरे जाते हैं, चाहे वह बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी हो या गैर-अर्थव्यवस्था वाली । कर रिटर्नस भरने से बाजार अर्थव्यवस्था वाले दर्जे या अन्यथा की पुष्टि नहीं होती है ।

ड.) दाहुआ का अनेक क्षेत्रों का संदर्भ जहां भारत में भी कीमत नियंत्रण विधमान है, गलत है। “बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश” में सरकार के नियंत्रणाधीन काम करने वाली किसी कंपनी और “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश” में सरकार के नियंत्रण के अधीन काम करने वाली किसी कंपनी को समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता है जैसा कि निर्यातक द्वारा इस मामले में प्रयास किया गया है ।

घ) याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि कंपनी एमईटी के लिए हकदार नहीं है । अन्य कंपनियों जिन्होंने चीन के साथ सहयोग किया है, में से कोई भी एमईटी के लिए हकदार नहीं है जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ठीक समझा गया है ।

#### ग. पाटन मार्जिन निम्न स्तर पर है :

याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उत्पादन लागत के सबसे उपयुक्त अनुमानों को देखते हुए प्रकटीकरण विवरण में आकलन किया गया पाटन मार्जिन निम्न स्तर पर है ।

#### घ. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में :

##### आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आकलन किए गए आयातों की वास्तविक मात्रा आयातों की ज्ञात मात्रा से काफी अधिक है जिसके लिए याचिकाकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था । वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा जांचों के दौरान यह तर्क दिया जा रहा था कि आयातों की वास्तविक मात्रा उन आयातों की मात्रा से काफी अधिक है जिनके लिए याचिकाकर्ता अधिप्रमाणिक रूप से साक्ष्य जुटा सकता था । आयातों की वास्तविक मात्रा का साक्ष्य प्रस्तुत करने में याचिकाकर्ता की कठिनाईयां इस तथ्य के कारण है कि इस संबंध में सूचना डीजीसीआई एंड एस के पास है जो व्यापार तथा उद्योग को सौदेवार आंकड़े प्रदान करने से इंकार कर रहा है ।

### घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए सेवा प्रभारों का अनुमोदन नहीं किया है। यदि ऐसी स्थिति है तो याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का भी समुचित रूप से समायोजन किया जाना अपेक्षित था क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भुगतान किए गए सेवाप्रभारों पर हुआ पारिश्रमिक शामिल है। याचिकाकर्ता इस बात को दोहराते हैं कि सेवा प्रभारों को छोड़कर क्षतिरहित कीमत की याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई निवल बिक्री वसूली संबंधी सूचना के साथ तुलना के परिणामस्वरूप अनुचित तुलना की स्थिति उत्पन्न होगी। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत संबंधी सूचना में देय सेवा प्रभार शामिल हैं और इसलिए लागत संबंधी सूचना में निहित बिक्री कीमत संबंधी सूचना में भी सेवा प्रभार शामिल है।

#### इ. क्षतिरहित कीमत के संबंध में

क) यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में प्रयोग किए गए तथ्यात्मक तत्वों का घरेलू उद्योग को खुलासा नहीं किया गया है लेकिन यह निवेदन किया गया है कि निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत अपेक्षित स्तर से काफी कम है जो वास्तविक लागत और लगाई गई पूँजी पर उचित आय पर आधारित है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि आकलन की गई क्षतिरहित कीमत की पुनः समीक्षा की जाए। याचिकाकर्ता को यह डर है कि निर्धारित क्षतिरहित कीमत का स्तर घरेलू उद्योग को तर्कसंगत राहत प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा।

#### च. निश्चित राशि आधार पर शुल्क

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निश्चित राशि के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। यह अनुरोध है कि अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश निश्चित राशि के आधार पर भी करने की कृपा करें।

### निर्यातकों के विचार

3.2 मैसर्स गुआक्सी दहुआ कैमिकल फैक्ट्री, चीन दहुआ को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जाएगा:

1. निर्यातकों ने कहा है कि उन्हें सामान्य प्रकटीकरण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करने हैं।

2. प्राधिकारी ने मैसर्स गुआक्सी दहुआ को इस आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान न करने का प्रस्ताव किया है कि प्रयाप्त सरकारी हस्तक्षेप के अभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह राज्य के स्वामित्व वाला एक उद्यम है। इस संबंध में उन्होंने यह कहा है कि चीन में सरकार के तीन स्तर केंद्रीय, प्रांतीय एवं शहर है। दहुआ शहर सरकार के स्वामित्व में है जिसका औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों बनाने में कोई भूमिका अथवा नियंत्रण जो भी हो नहीं है। शहर सरकार की भूमिका को प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकार की भूमिका के साथ आमित नहीं किया जाएगा। शहरी सरकार एक स्थानीय नागरिक निकाय है जिसके पास उन बाजार की दशाओं जिनमें कोई उद्योग करता है, को प्रभावित करने वाली औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों का सीमित क्षेत्र होता है। शहरी सरकार मूल रूप से नागरिक सुविधाओं की देख-रेख करती है न कि औद्योगिक /आर्थिक नीतियों की। इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण ‘प्रांतीय’ अथवा केंद्रीय सरकार जो भी मामला हो द्वारा किया जाता है। जहां तक दहुआ का संबंध है, शहरी सरकार मूलरूप से एक निवेशक अथवा उद्यम है। अतः बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार को दहुआ को प्रदान करने से मना नहीं किया जा सकता है।

3. दहुआ ने दस्तावेजी प्रमाण के साथ पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि कीमत, लागत एवं कच्ची सामग्रियों समेत निविष्टियों, लागत प्रौद्योगिकी एवं श्रम, उत्पादन, बिक्रियों एवं निवेशों के बारे में निर्णय आपूर्ति एवं मांग को प्रदर्शित करने वाले बाजारी संकेतकों के अनुरूप लिए जाते हैं और यह कि इस बारे में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है।

4. विना यह स्वीकार किए कल्पना भी करना कोई हस्तक्षेप था, यह बात नोट की जानी चाहिए कि स्वयं नियम हस्तक्षेप की कुछ सीमा की अनुमति देते हैं किंतु वे सरकार की ओर से

किसी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं। वर्तमान मामले में, सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है।

5. इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी का निर्णय दहुआ को बाजार अर्थव्यवस्था वाले सिद्धांतों पर कार्य करने वाला एक उद्यम नहीं मानता है, जो कानूनी रूप से बुरा है। दहुआ एक बार पुनः प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार कर उन्हे बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करें।

6. प्राधिकारी ने कच्ची सामग्रियों, उपयोगिताओं और क्षमता उपयोग जमा बिकी लागतों पर 5% उचित लाभ के बारे में समुचित समायोजन करने के पश्चात भारत में सर्वाधिक दक्ष उत्पादक के उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य (सीएनबी) का निर्धारण किया है। मैसर्स गुआवसी दहुआ अनुरोध करता है कि उपर्युक्त विधि विज्ञान भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित तीन विधि विज्ञानों में से एक नहीं है। सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया जाएगा। इसके मद्देनजर दहुआ यह निवेदन करता है कि प्राधिकारी उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करें।

#### क्षति निर्धारण एवं कारणात्मक संबंध के बारे में:

1. प्रारंभिक जांच परिणामों के पैराग्राफ 9.1 और प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 1 दिए आयात आंकड़ों में भिन्नता है जहां तक उनकी जांच अवधि से संबंध है। प्रारंभिक जांच परिणामों में चीन से हुए आयात 2040 मी./टन दर्शाए गए हैं जो प्रकटीकरण विवरण में संशोधित कर 6362 मी./टन दर्शाए गए हैं इसी प्रकार, अन्य देशों से किए गए आयात प्रारंभिक जांच परिणामों में 2505 मी./टन सूचित किए गए हैं जो प्रकटीकरण विवरण में 2192 संशोधित करके कम दर्शाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संशोधन आई वी आई एस, मुंबई के सौदे-वार विवरणों की अभिवृद्धि और अध्याय 32 के अंतर्गत डीजीसीआईएण्डएस द्वारा दी गया सूचना के कारण है।

2. दहुआ इस संशोधन का विरोध नीचे वर्णित तीन आधारों पर करता है :-
- क) ऐसा प्रतीत होता है कि घेरलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् अतिरिक्त आंकड़े दिए हैं। ये अतिरिक्त आंकड़े सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में किए गए लिखित अनुरोध का हिस्सा नहीं थे। एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में हमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों में संशोधन करने के बारे में, कोई जानकारी नहीं दी गयी है। हमें इन संशोधित आंकड़ों की जांच कर उन पर अपनी टिप्पणियां देने का अवसर नहीं दिया गया है।
- ख) प्रथम दृष्ट्या यह संशोधन अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि अध्याय 2823.00 के अंतर्गत एक विशिष्ट शीर्ष है। शीर्ष में यह उल्लेख है : 2823.00 टाइटेनियम ऑक्साइडस।
- ग) शीर्ष 3206 टाइटेनियम ऑक्साइडस के आधार पर केवल पिग्मेंट्स और उनके उत्पादों को शामिल करता है। इसमें स्वयं टाइटेनियम ऑक्साइडस शामिल नहीं है। विचाराधीन इसमें स्वयं टाइटेनियम ऑक्साइडस शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद टाइटेनियम ऑक्साइडस है न कि टाइटेनियम ऑक्साइडस पर आधारित पिग्मेंट्स। क्योंकि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि टाइटेनियम ऑक्साइडस की निकासी ‘माइका पिग्मेंट्स’ के नाम पर की गयी है वह भी आयात आंकड़ों में दिए गए ब्यौरे के आधार पर। प्राधिकारी टाइटेनियम ऑक्साइड के आयातों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित पिग्मेंट्स के आयातों को शामिल नहीं कर सकता है। इसके अलावा, इससे सीमा शुल्क विभाग के समक्ष गलत धोषणा किए जाने का आरोप भी लगता है। पाटनरोधी जांच में इस प्रकार के आरोपों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है।
- घ) प्राधिकारी ने यह कहा है कि अध्याय 32 के अंतर्गत आई वी आई एस, मुंबई के अनुसार सौदेवार ब्यौरे और अध्याय 32 के तहत डीजीसीआई एण्ड एस के अंतर्गत प्रदर्शित आयात जोड़े गए हैं। यह मामला दो बार जोड़े जाने का प्रतीत होता है। यह ज्ञात नहीं है कि आईवीआईएस द्वारा अध्याय 32 के अंतर्गत सूचित उन्हीं सौदों को अध्याय 32 के अंतर्गत डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों के लिए भी सूचित किया गया है। यह भी संभव है कि डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा अध्याय 28 के अंतर्गत सूचित सौदों को आई वी आई एस, मुंबई और विलोमतः द्वारा अध्याय 32 के अंतर्गत सूचित किया गया होगा। अतः आयातों की कुल मात्रा निकालने के लिए दो विभिन्न श्रोतों के आंकड़ों को मिलाना सही नहीं है। प्राधिकारी को या

तो डी जी सी आई एण्ड एस के आंकड़ों को अपनाना चाहिए अथवा आई बी आई एस, मुंबई के आंकड़ों को न कि दोनों के संयोजन को।

5. इस प्रकार, भारत में आयातों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त वास्तविक आधार सही नहीं है अभी जांच परिणाम उस सीमा तक निष्प्रभावी हो जाएगा। दहुआ प्राधिकारी से आयातों की मात्रा का निर्धारण करने और क्षति का पुनर्निधारण, इत्यादि करने का अनुरोध करते हैं। हमारी टिप्पणियों के लिए संशोधित प्रकटीकरण विवरण हमें उपलब्ध कराया जाय।

च. प्रारंभिक जांच परिणामों एवं प्रकटीकरण विवरण के बीच क्षमता उपयोग में व्यापक अंतर आ चुका है।

#### कम कीमत पर बिकी और कीमत में कटौती समान है

क. प्राधिकारी ने यह पाया है कि कीमत कटौती 10-20 प्रतिशत की सीमा में थी। इसके अलावा, प्राधिकारी को यह मालूम हुआ है कि कम कीमत पर बिकी की सीमा भी 10-20 प्रतिशत ही है। जब कम कीमत पर बिकी हुयी कीमत कटौती एक समान सीमा में है तो, घरेलू उद्योग की नुकसानरहित कीमता और बिकी वसूली या तो समान होगी अथवा काफी निकट होगी। इन परिस्थितियों में, घरेलू उद्योग को हुई अति प्रमाणित नहीं की जा सकती है। अतः क्षति निर्धारण अभी कारणात्मक संबंध का अभाव माना जाएगा।

#### बिकी कर के प्रभाव पर कारणात्मक संबंध विश्लेषण में विचार नहीं किया गया है :

(क) टी टी पी एल द्वारा के एस आई पी टी सी को की गयी बिकी में 30 प्रतिशत की दर पर स्थानीय बिकी कर शामिल था जबकि दूसरी बिकी के एस आ पी टी सी द्वारा अंतिम उपभोक्ता को की गयी थी जिसमें 4 प्रतिशत की दर पर सी एस टी की लेवी शामिल थी। जब केरल सरकार द्वारा इस शर्त में ढील देते हुए टी टी पी एल को अल्पावधि के भीतर उत्पाद की सीधे बिकी करने की अनुमति दी है तो ग्राहकों ने टी टी पी एल से खरीदना शुरू कर दिया है और टी टी पी एल ने अपना सारा स्टॉक निकाल दिया है। इस प्रकार यह क्षति टी टी पी एल द्वारा अपनी गयी इस विशेष पद्धति के कारण हुई है न कि पाटित आयातों

से। इस तथ्य की जांच नहीं की गई है।

### 3.3 मैसर्स कांग वु शुंगफेंग टाइटेनियम ऑक्साइड कं0 लि0, चीन

मै0 कांग वु ने ईमेल द्वारा अनुरोध किया है कि “मैसर्स कांग वु शुंगफेंग टाइटेनियम ऑक्साइड कं0 लि0, चीन” “मैसर्स डेझियांग प्रोविन्सियल लाइट एण्ड टेक्सटाइल ग्रुप लाइट इण्डस्ट्री कं0 लि0” के जरिए निर्यात करता है और सत्यापन के दौरान एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

घरेलू कीमतों पर आधारित पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 26.9 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत के लगभग निकाला जाएगा।

### आयातकों के विचार

#### 3.4 मैसर्स कैमी इंटरप्राइज

आयातक/प्रयोक्ता ने दिनांक 14.07.2003 के अनुरोध द्वारा यह अभ्युक्तियां प्रस्तुत की है कि:-

- क) क्षति विश्लेषण केवल टीटीपीएल से संबंधित है और जांच अवधि अर्थात् 1.1.2002 से 31.12.2002 के दौरान इसकी बिक्री कीमत दोहरे कराधान के अधीन थी।
- ख) घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में गिरावट आने का कारण यह हो सकता है कि जांच अवधि के दौरान और इससे पहले भी संवद्ध सामग्री की पर्याप्त मात्रा का आयात चीन से किया गया होगा और विभिन्न निर्यात संवर्धन स्टॉमों के अंतर्गत शुल्क मुक्त निकासी कर घरेलू बाजार में बेचा गया होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि वे घरेलू उत्पादन के 75 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं और वास्तविक उत्पादन एवं उसकी संगतता की जांच करनी आवश्यकत है तथा शेष की आपूर्ति कैसे की जाती है मांग भी कैसे पूरी की जाती है।
- घ) पाटनरोधी शुल्क लगाने से वास्तव में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है और घरेलू उपभोगताओं को उपलब्ध विकल्प में भी कमी आ रही है।

ड.) सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार पर कीमत तथा पाटन मार्जिन नहीं दिया गया है और इसलिए यह मानना उचित है कि पाटन शुल्क कल्पनाओं और समग्र रूप से लगाया गया है।

मै0 केमी ऐन्टरप्राइजेज, ने दिनांक 25:8.2003 के अपने अनुरोध में कहा है कि :-

क) टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस ग्रेड एक सामान्य नाम है और इसलिए तुलना की गई वस्तुएं एक समान नहीं हैं क्योंकि ये गुणवत्ता प्रतिष्ठा, ट्रेड मार्क की मौजूदगी एवं उद्गम के देश एवं अनुप्रयोग की दृष्टि से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आई एस आई (बी आई एस) मानकों के अनुसार मानकीकृत किया जाता है और उनका अजन्तांक्स ए ॥। : 1991 नामक एक ब्रांड है और इसलिए यह आयातित चीनी माल के साथ तुलनीय नहीं है।

ख) चीन में विनिर्मित टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस ग्रेड घरेलू रूप से उत्पादित माल के स्तर के बराबर का नहीं है। घरेलू रूप से उत्पादित माल अपनी गुणवत्ता और प्रचलन के कारण चीनी माल से अधिक कीमत पर विकला है।

ग) गुणवत्ता में भिन्नता के मद्देनजर घरेलू रूप से उत्पादित माल हमेशा चीनी माल से अधिक कीमत पर विकला है और बिक्री कीमत में अंतर इतना अधिक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो।

घ) टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस का भिन्न भिन्न देशों से आयात किया जाता है और इसकी कीमत एक समान नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक ब्रांड की कीमत गुणवत्ता प्रतिष्ठा, प्रचलन और अनुप्रयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

ड) जांच की शुरुआत के बाद याचिकाकर्ता ने विपणन मध्यस्थ ( के एस आई पी टी सी) का साथ छोड़ दिया है और दोहरे कराधान से बचा है और उसने अपने स्टॉकिस्टों को छूटें प्रदान की और बिकियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और तंत्यश्चात अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू होने के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी थीं और इस प्रकार याचिकाकर्ता या श्रमिक के बजाय केवल स्टॉकिस्ट को लाभ हुए।

- च) प्रत्याशित मांग 8,400 एम/टी का भावी अंतर दर्शाती है और इस प्रकार यह एनाटेस ग्रेड टाइटेनियम की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर है तथा इसलिए याचिकाकर्ता को क्षति या क्षति की आशंका का सवाली ही नहीं उठता है और चीन से ऐसे कम मात्रा में शुल्क चुकाए गए आयातों ज्ञो कि नगण्य है के कारण भविष्य में उनके किसी भी समय बंद होने की कोई संभावना नहीं है। 2001-2002 की अवधि के लिए एनाटेस ग्रेड टिटेनियम का अनुमानित मांग स्तर 22,500 एम/टी है।
- छ) टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस ग्रेड के समेकित आयात वर्ष 2001-2002 के दौरान अधिकतम 2,200 थे और अप्रैल 2002 से जुलाई 2002 के दौरान न्यूनतम 1,500 एम/टी थे।
- ज) अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए एनाटेस ग्रेड टाइटेनियम के भारतीय विनिर्माता एवं उत्पाद स्तर।
- झ) प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई जांच को उपरोक्त कारण के मद्देनजर समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अनंतिम रूप से लागू पाटनरोधी शुल्क को न्याय और उचित प्रतियोगिता की स्थापना की दृष्टि से हटा लिया जाना चाहिए।

#### घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

4.0 इन जांच परिणामों के निर्धारण के समय निर्यातकों, आयातकों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच एवं उन पर विचार किया गया है और जहां भी उपयुक्त समझा गया इन पर इसके बाद विचार किया गया है। तथापि, भिन्न भिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दों की निम्नानुसार जांच की गई है:-

- क) क्षतिरहित कीमत के निर्धारण और निवल बिक्री प्राप्ति के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि का चयन किया और इसमें अपनायी गई पद्धति का विवरण दिया गया था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया था कि क्षति रहित कीमत की निवल बिक्री प्राप्ति और पहुंच मुल्य के साथ उचित तुलनीय स्तरों तक तुलना की गई थी।

### विचाराधीन उत्पाद के मुद्रे के संबंध में

विचाराधीन उत्पाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस, ग्रेड उप शीर्ष 28230001 अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद यह सामने आया है कि अध्याय 32 के अंतर्गत भी भारी मात्रा में आयात किए गए हैं। प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए अध्याय 28 के तकत आयातों और जनवरी से मार्च, 2002 की अवधि के लिए अध्याय 32 के तहत तथा अप्रैल से दिसम्बर 2002 तक की अवधि के लिए डी जी आई एण्ड एस, कोलकाता से आई एण्ड एस आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डी जी आई एण्ड एस, कोलकाता से अध्याय 28 और 32 के लिए आयातों संबंधी सौदेवार व्यौरे की मंगवाये हैं जिन्हें प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात अध्याय 32 के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के भारी मात्रा में आयातों की जानकारी मिली है। इस परिस्थितियों में प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजनार्थ टाइटेनियम\* डाइऑक्साइड एनाटेस टाइप के संबंध में अध्याय 28 और 32 के अंतर्गत बताई आयात मात्राओं पर विचार किया है और यह सुनिश्चित किया कि उन के विश्लेषण में आयातों की दोहरी गणना से बजा जा सके।

### मैटो केमी एन्टरप्राइज द्वारा समान वस्तु के मुद्रे के संबंध में

आयातक/प्रयोक्ता ने यह मुद्रा उठाया है कि घरेलू माल अजन्टोक्स नामक उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांड है, इसकी तुलना में चीन का माल निम्न गुणवत्ता का है और कम कीमत पर उपलब्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मात्र एक निराधार तर्क है। इसके अलावा वह नोट करते हैं कि किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में गुणतत्त्व ब्रांड का मुद्रा नहीं उठाया है। इस प्रकार, आयातक/प्रयोक्ता द्वारा दिए गए तर्क को अस्वीकार किया जाता है।

जांच अवधि के दौरान अग्रिम लाइसेंस/अनेक नियति संवर्धन स्कीमों के तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के शुल्क मुक्त आयातों के बारे में दिए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि डी टी ए के, तहत घरेलू बाजार में आने वाली संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क सहित सभी शुल्क लगाए जाते हैं।

जर्मनी समेत विभिन्न देशों के लिए आयात मात्राएं दर्शनी वाला पाई चार्ट के रूप में दिया गया साक्ष्य अप्रैल 1998 से मार्च 1999 तक की अवधि के लिए है और जांच अवधि के लिए नहीं है। इसलिए प्राधिकारी इस साक्ष्य को अस्वीकार करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडस्ट्रीयल कैमिकल एण्ड साल्वेंट (चेन्नई) द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 2002 को यथा प्रस्तुत बाजार कीमत संबंधी उद्घरणों में यह संकेत/स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का आयात शुल्क मुक्त स्कीमों के तहत किया गया है।

जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा संबद्ध वस्तु की बिक्री दोहरे कराधान के अधीन थी और उनकी बिक्री कीमत अप्रतिस्पर्धी थी के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीटीपीएल अपने उत्पादों को जांच अवधि से पहले भी और जांच अवधि के दौरान भी एक ही इकाई के जरिए बेच रहे थे।

#### मै0 दहुआ को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने संबंधी के दावों के संबंध में

दिनांक 6 जून 2003 के प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8.1 में प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण का संदर्भ दिया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 दहुआ ने साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की है जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे संबंधी दावा किया गया है, तथापि, प्राधिकारी संबंधित नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 1 से 6 तक में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ हैं और अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्य करने को बाध्य है जिसके तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण, भारत में समान वस्तु की तर्कसंगत लाभ सहित दी गई या देय वास्तविक कीमत समेत किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर किया जाता है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार मै0 दहुआ के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे संबंधी इन निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ नियति के द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई है जिनके आधार पर बाजार बिक्रियों, उत्पादन लागत और बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे संबंधी जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने अपने अनुरोध में स्वीकार किया है कि दहुआ एक राज्य के स्वामित्व वाली उद्यम है जो चीन जनवादी गणराज्य के औद्योगिक उद्यमों और राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिक उद्यमों के प्रचालन तंत्र के रूपान्तरण संबंधी विनियम एवं कानून द्वारा शासित है। वैस सिटी सरकार, गुआंगसी प्रदेश इस उद्यम की अकेली शेयर धारक कंपनी है। तदनुसार, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि इस मामले में राज्य के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की अनुपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

और इस प्रकार यह नियमों के अंतर्गत दिए गए मापदंडों को पूरा नहीं करता है। इसी कारण, प्राधिकारी ने इस कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान नहीं किया है।

#### (घ) प्राधिकारी द्वारा जाँचः

4.0 निर्यातकों, आयातकों, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए निवेदनों का इन जाँच परिणामों हेतु परीक्षण किया गया है तथा उचित स्थानों पर उन पर कार्रवाई की गई है। तथापि, विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का निम्नानुसार परीक्षण किया गया है:-

i) हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए गोपनीयता के मुद्दे पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो सूचना गोपनीय स्वरूप की होती है उसे गोपनीय माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुसार ऐसी सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा किया जाता है उसे गोपनीय सूचना माना एवं निरुपित किया जाता है। आगे ऐसी सूचना जिसे गोपनीय माना गया है तथा जिसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, को भी गोपनीय निरुपित किया गया है।

#### (ड.) विचाराधीन उत्पाद

5.0 (क) वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस ग्रेड है जिसका रासायनिक फार्मूला टीआईओ2 है।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस रूप या रूटाइल रूप में हो सकता है। तथापि, वर्तमान जाँच मात्र टाइटेनियम डाइऑक्साइड के एनाटेस रूप के बारे में है।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस का उत्पादन इल्मेनाइट से किया जाता है जो कि टाइटेनियम केरस आयरन तथा फेरिक आयरन का मिश्रण है। इल्मेनाइट से टाइटेनियम इस कच्ची सामग्री की सल्फ्युरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। 'घोल' में टाइटेनियम ऑक्सी एल्फेट डाला जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को टाइटेनियम ऑक्सी एल्फेट से भाष प्रविष्ट कर तथा संसाधित पत्त्य के निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड सामान्यतः ऑक्साइड रूप में मिलता है। संबद्ध वस्तु की विशेषताओं का अपवर्ती निर्देशक, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, कड़ापन, क्रिस्टल संरचना, तेल अवशोषण, रंग, विलोपन शक्ति, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश अवशोषण, चॉकिंग का प्रतिरोध आदि के रूप में वर्णन किया गया है।

(ग) टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक रसायन है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क टैरिफ तथा आई.टी.सी के अंतर्गत उत्पाद का पूर्ण वर्णन निम्नानुसार है:-

अध्याय/उपशीर्षक	विवरण
28	अकार्बनिक रसायन
2823	टाइटेनियम डाइऑक्साइड
282300	टाइटेनियम ऑक्साइड
28230001	टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एनाटेस टाइप

यद्यपि उत्पाद का एक अपना वर्गीकरण है, डी.जी.सी.आई.एंड.एस. के सौदेवार आयात आंकड़ों से यह पता चलता है कि उक्त उत्पाद सीमा शुल्क वर्गीकरण 3206 के अंतर्गत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्राधिकारी ने पाया है कि उत्तर देने वाले दो निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात भी डी.जी.सी.आई.एंड.एस. द्वारा सूचित 2823 वर्गीकरण के तहत आने वाले आयातों के क्षेत्र में हुए हैं।

(घ) टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक रंजक है और इसका उपयोग प्राथमिक रूप से पेंट्स, प्लास्टिक्स, पेपर, स्थाही, रबड़ आदि कि विनिर्माण में किया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है:-

- पेंट के सभी प्रकार के सफेद एवं पेस्टल शेडों में,
- व्हाइट वॉल्ड टायरों तथा कार के टायरों में,
- प्रिंटेड वस्त्रों में,
- इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में,
- फुटवियर तथा चर्म सामग्रियों में,
- लिनोलियम, सफेद मोजैक जैसी फ्लोरिंग सामग्रियों में,
- वस्त्र उद्योग में कृत्रिम फाइबर की चमक को कम करने में।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड (एनाटेस) में सफेदी की बहुत उच्च मात्रा होती है। इसकी रंग सोखने की क्षमता और विलोपन शक्ति किसी दूसरे रंजक से बेहतर होती है और इसमें प्रकाश और ताप के विरुद्ध भी संतुलन क्षमता एवं स्थायित्व होता है। यह टॉक्सिक नहीं है। इस उत्पाद का आयात ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत अनुमत्य है।

### (च) समान वस्तु

6.0 याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु चीन से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन से निर्यातित टाइटेनियम डाइऑक्साइड और याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित टाइटेनियम डाइऑक्साइड में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

यह जाँचने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित, टाइटेनियम डाइऑक्साइड तुलनीय है, उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगिता, उत्पाद विशेषताएं, कीमतीकरण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं पर विश्वास किया गया था। यह मालूम होता है कि चीन से आयातित संबद्ध वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। इस बारे में याचिकाकर्ता के दावों के विरोध में कोई तर्क नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की तरह समान वस्तुएं हैं।

### (छ) घरेलू उद्योग:

7.0 देश में टाइटेनियम डाइऑक्साइड (एनाटेस) ग्रेड के तीन उत्पादक हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड (एनाटेस) का एक और उत्पादक, केरल मिनरल एण्ड बेटल्स लिमिटेड है। तथापि कंपनी केवल रुटाइल ग्रेड का उत्पादन करती है। सभी उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं। याचिका संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों समेत एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है। मै0 ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लि�0, ट्रावनकोर एक याचिकाकर्ता कंपनी है जिसने याचिका में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

अन्य दो उत्पादकों अर्थात् मै0 कोलमैक कैमिकल्स लि0 और किलबर्न कैमिकल्स लि0 ने याचिका का विशेष तौर पर समर्थन किया है।

जांच शुरू करने के बाद मै0 कोलमैक कैमिकल्स ने क्षति संबंधी संगत सूचना के साथ लागत संबंधी सूचना भी उपलब्ध कराई है। केवल ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोटक्ट्स का भारतीय उत्पादन 50% से अधिक बनता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता नियम 5(1),5(3) और नियम 5(3) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं। आगे, नियम के अर्थ के भीतर ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोटक्ट्स तथा कोलमैक कैमिकल्स को “घरेलू उद्योग” माना गया है।

**(ज) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन**

8.0 धारा 9क(1)(ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- i सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप धारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या
- ii जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की समुचित तुलना नहीं हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य या तो
- iii निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या
- iv उपधारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित प्रशासनिक विक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत:-

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहाँ वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं

होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो, तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के बारे में 15 जुलाई 1999 की सं. 44/99 (एनटी), 31 मई 2001 की सं. 28/2001 (एनटी) और 4 जनवरी 2002 की सं. 1,2001 (एनटी) की विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं को भी नोट किया है।

प्राधिकारी ने उपर्युक्त धारा के अनुसार संबद्ध देशों के निर्यातकों को जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने एवं अपने विचार प्रकट करने, यदि कोई हो, के लिए अवसर प्रदान किया था। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी लिखा था। प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के धारा 9क(1)(ग) के अनुसार निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी। चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित निर्यातकों से उत्तर प्राप्त हुए थे:-

- (क) मै0 गोऑग्सी दहुआ केमिकल फैक्ट्री, चीन (दहुआ);
  - (ख) मै0 गोऑग्सी जिंग में जियाँग टाइटेनियम डाइआक्साइड कं0लि0, चीन;
  - (ग) मै0 गोऑग काँग वू टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग कं0लि0, चीन;
  - (घ) मै0 शौगन केमिकल प्लान्ट, चीन;
- सामान्य मूल्य तथा कारखाना द्वारा निर्यात कीमत के निर्धारण का विवरण नीचे दिया गया है।

मै0 गोऑग्सी दहुआ केमिकल फैक्ट्री, चीन (दहुआ):

निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली में सूचना उपलब्ध कराई है। घरेलू बाजार में बिक्री, भारत को निर्यात, भारत तथा घरेलू बाजार को निर्यातों के लिए बिक्री कीमत ढांचा, फैक्ट्री लागत तथा लाभ के संबंध में सौदेवार सूचना क्रमशः परिशिष्ट 1-8 में उपलब्ध कराई गई है।

मै0 दहुआ ने अपने निवेदनों में यह दावा किया है कि कंपनी बाजार आर्थिक सिद्धांतों पर कार्य करती है। उन्होंने अनुरोध किया है कि गोऑग्सी दहुआ केमिकल फैक्ट्री पाटनरोधी नियमों के पैराग्राफ 8(3) के अंतर्गत निर्धारित चारों शर्तों को पूरा करता है और इस प्रकार यह पैराग्राफ 8(3)

के प्रावधान के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी के रूप में माने जाने योग्य है और इन स्थितियों के अंतर्गत जहां तक इस कंपनी का संबंध है प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन के मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनुबंध 1 के पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करेंगे।

प्रारंभिक जांच में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि वे उपर्युक्त नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 1 से 6 तक में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते और अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्रवाई करने को बाध्य हैं जिसके द्वारा उचित लाभ मार्जिन मिल करने के लिए विधिवत समायोजन समान उत्पाद के लिए भरत में वास्तविक रूप से अदा की गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर समान मूल्य निर्धारित किया जा सकता हो।

मैओ गोऑर्गसी दहुआ केमिकल फैक्ट्री, चीन ने 01.09.2003 के अपने निवेदनों के अनुसार बाजार आर्थिक स्थिति का पुनः दावा किया है।

कंपनी इस विषय पर प्रारंभिक जांच निष्कर्ष से असहमत है। दहुआ पुनः दावा करता है कि अंतिम जांच परिणाम में बाजार आर्थिक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का परिकलन उसकी स्वयं की कीमतों एवं लागतों पर किया जाना चाहिए। यह निवेदन विशेष रूप से प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 8.1 के संदर्भ में सामान्य मूल्य के मुद्दे के विषय में है।

#### दहुआ में प्रचलित बाजार स्थितियां

यह दावा किया गया है कि उसे निवेश/उत्पादन, कीमत निर्धारण, निर्यात, घरेलू बिक्री, प्रचालन, कार्मिक निवेश तथा प्रचालन संबंधी अन्य मुद्दों के साथ-साथ पर्याप्त साक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण है। तदनुसार, दहुआ, प्रारंभिक जांच अधिसूचना के पैरा 8.1.3 के उप-पैरा (3) में दिए गए उन मानदंडों को पूरा करता है।

यह भी दावा किया गया है कि दहुआ प्रतिस्पर्धात्मकता के श्रेष्ठ स्रोतों का चुनाव करता है। बाजार स्थिति तथा उत्पादन जरूरतों के आधार पर दहुआ ने संविदा अथवा स्पॉट बाजार द्वारा अपेक्षित माल के अलग-अलग आयुर्तिकर्ताओं का चुनाव किया है। प्रत्येक मद की कीमतों, स्वामित्व

तथा पतों सहित समस्त आपूर्तिकर्ताओं की सूची उपलब्ध कराई गई है। तथापि, ये आपूर्तिकर्ता, निजी अथवा राज्य स्वामित्व वाले, सभी बाजार स्थितियों के अंतर्गत प्रचालनरत हैं। दहुआ के लिए एकमात्र विचारणीय बात अपनी कच्ची सामग्री की कीमत एवं गुणवत्ता है, जो वे प्रदान कर रहे हैं। दहुआ ने जांच अवधि के दौरान किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता का चयन नहीं किया है।

- (i) दहुआ ने एक निजी कंपनी से कोल गैस तथा 6 कंपनियों से कोयले की खरीद की है जिनमें से 4 निजी स्वामित्व वाले हैं। इसके अलावा, दहुआ ने किसी पार्टी से पानी का क्रय नहीं किया है बल्कि स्वयं ही उसका उत्पादन किया है। जांच अवधि के दौरान दहुआ के उत्पादन के लिए उपयोगिताओं के आपूर्तिकर्ता के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराई गई है। उपयोगिताओं के इस्तेमाल के लिए दहुआ पर सामान्य प्रभार लगाया गया है। दहुआ की जानकारी में उपयोगिताओं के इन आपूर्तिकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है।
  - (ii) लागत एवं गुणवत्ता को देखते हुए दहुआ ने विदेशी बाजार से आयात करने के स्थान पर सभी आवश्यक कच्ची सामग्री की खरीद घेरेलू बाजार से की है। इस संबंध में दहुआ पर कच्ची सामग्री के आयातों पर कोई प्रतिबंध या शर्तें नहीं लगाई गई हैं।
  - (iii) सामान्यतः, दहुआ संविदा के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करता है। संविदात्मक कर्मचारियों को सामान्यतः विशिष्ट उत्पादन प्रवाह के लिए, प्रति सप्ताह केवल 40 घंटे कार्य करने के लिए रखा जाता है। उनकी नियुक्ति के पूर्व कर्मचारियों को सख्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इलेक्ट्रीशियनों तथा वेल्डरों जैसे कुछ विशिष्ट पदों के लिए संगत प्रमाण पत्र/योग्यताएं अपेक्षित हैं।
  - (iv) कीमत निर्धारण एवं उत्पादन गुणवत्ता के संबंध में निर्णय लेने के लिए दहुआ पूर्णतः स्वतंत्र है। दहुआ के उत्पाद विनिर्माण तथा बिक्री की प्रक्रिया में कोई स्थानीय/क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा राज्य, कानूनी अथवा सामान्य तौर पर शामिल नहीं है।
  - (v) गोआंगसी गुईकिसनचेंग अकाउंटिंग फर्म द्वारा दहुआ के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा आय विवरण को प्रति वर्ष स्थानीय कराधान प्रशासन तथा वित्तीय प्रशासन में पंजीकृत कराना आवश्यक है।
- (क) दहुआ द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के वित्त मंत्रालय द्वारा 1992 में अधिनियमित उद्यमों के लिए वित्तीय प्रणाली, औद्योगिक उपकरणों के लिए वित्तीय प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों, उद्यमों के लिए लेखा मानकों तथा औद्योगिक उपकरणों के लिए लेखा प्रणाली को लागू किया जाता है।

(ख) दहुआ ने अपनी अचल, अथवा चल संपत्तियों की खरीद, किसी अन्य सरकारी एजेंसियों अथवा अन्य उपकरणों से मुफ्त अथवा छूट के साथ प्राप्त करने के स्थान पर खुले बाजार से की है। उदाहरण के लिए दहुआ ने खुले बाजार से उपकरण, मशीनी यंत्र तथा अन्य उत्पादन उपकरण की खरीद खुले बाजार से की है; तथा दहुआ तथा निर्माता कंपनियों के बीच संविदात्मक निर्माण के द्वारा बिल्डिंगों की प्राप्ति की है। दिनांक 31 दिसम्बर 2002 के दहुआ के अचल/चल संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं।

(vi) दहुआ ने उत्पादन और/अथवा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोई सुविधा लीज अथवा किराए पर उपलब्ध नहीं कराई है।

(vii) 31 दिसम्बर 2002 तक दहुआ ने बैंक ऑफ चायना बेज ब्रांच तथा इंडस्ट्रियल तथा कमर्शियल बैंक ऑफ चायना बेज ब्रांच से ऋण लिया था। दहुआ को ऋण देने वाले दोनों बैंक वाणिज्यिक बैंक हैं और बाजार आर्थिक स्थितियों के तहत प्रचालनरत हैं। दहुआ को कोई विशेष ऋण अथवा आर्थिक सहायता योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। दहुआ द्वारा वर्ष 2002 तक लिए गए ऋणों की सूची उपलब्ध कराई गई है।

(viii) विदेशी विनिमय प्रबंधन विनियमन के तहत, आर.एम.बी. तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर बाजार की आपूर्ति - मांग तंत्र पर आधारित है तथा, केवल एक, व्यवस्थित फ्लोटिंग दर है। पीपल्स बैंक ऑफ चायना, जो सेंट्रल बैंक है, इंटर-बैंक एक्सचेंज मार्केट की कीमतों के अनुरूप दैनिक विनिमय दरों का प्रकाशन करता है।

इस प्रणाली के अनुसार, दहुआ सौदे की तारीख की दर पर निवेशों के खरीद के लिए आर.वी.एम. के साथ बैंकों से विदेशी मुद्रा की खरीद कर सकता है। इसी प्रकार दहुआ बैंकों को अपने अर्जन का विक्रय सौदे की तारीख की दर पर विदेशी मुद्रा में किया है। तथापि, दहुआ वैश्विक बाजार में नया है तथा उसने अब तक विदेशी मुद्रा खाते के लिए आवेदन नहीं दिया है।

(ix) दहुआ ने पिछले पांच वर्षों में विनिमय व्यापार अथवा प्रति-व्यापार नहीं किया है।

(x) दहुआ ने पिछले पांच वर्षों में भी विनिमय व्यापार अथवा प्रति-व्यापार नहीं किया है।

## 2. बाजार आर्थिस्थिति के लिए कानूनी मानदंड

दहुआ ने बाजार आर्थिक स्थिति के लिए मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने पहले दो वें में भारत के पाठनरोधी नियमों तथा चीन के डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल करने संबंधी प्रोटोकोल का संदर्भ लिया है। दहुआ का विश्वास है कि उनके विनिर्माण, उत्पादन तथा संबद्ध उत्पाद की विक्री वाणिज्यिक प्रयोजनों पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से बाजार संकेतकों को दर्शाते हैं।

प्रारंभिक जांच परिणामों की अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह भी उल्लेख किया था कि संगत कानूनों तथा विनियमों में “अनिवार्य योजना” तथा “नीतिगत हानि” जैसे कुछेक पाठ/वाक्यांशों से यह पता चलता है कि दहुआ उपर्युक्त नियम के अनुबंध 1 के पैरा 8 में की गई परिकल्पना के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन नहीं कर रहा है। दहुआ उससे सहमत नहीं हो सका। वस्तुतः अनिवार्य योजना चीन के अधिकांश वाणिज्यिक क्षेत्रों में काफी पहले समाप्त हो गई है तथा उत्पादों पर कीमत नियंत्रण में भारी कमी की गई है। डब्ल्यू.टी.ओ. के एक सदस्य के रूप में भी चीन उत्पादों अथवा सेवाओं पर कोई कीमत नियंत्रण शुरू नहीं करने के लिए बाध्य है बशर्ते कि चीन जनवादी गणराज्य के शामिल होने संबंधी प्रोटोकोल के अनुबंध 4 में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है तथा वह चीन के शामिल होने संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के पैरा 56 में किए गए स्पष्ट उल्लेख के अनुसार उनमें भविष्य में कमी न करने के लिए भी बाध्य है। दहुआ द्वारा संबद्ध उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रयुक्त कच्ची सामग्री तथा स्वयं संबद्ध उत्पाद दोनों ही चीन के प्राधिकरण द्वारा सरकारी कीमत नियंत्रण की सूची में नहीं आते हैं।

निर्यात कार्यकलापों के अनुसार चीन ने निर्यात कार्यकलापों संबंधी नियंत्रण में काफी कमी की है और उसने सामान्यतः 1990 से ही वस्तुओं के मुक्त आयात एवं निर्यात की अनुमति दी थी। चीन जनवादी गणराज्य के विदेश व्यापार कानून के अनुच्छेद 15 “विदेश व्यापार कानून” के अनुसार “राज्य वस्तुओं और प्रोटोगिकी के मुक्त रूप से आयात की अनुमति देता है।” इसके अलावा वस्तुओं के निर्यात से संबंधित एक नये विनियमन को चीन के डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने से एक दिन पहले जारी किया गया था जिसमें मुक्त, उचित एवं व्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी गई है। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से संबंधित चीन जनवादी गणराज्य के विनियमन के अनुच्छेद 4 (“वस्तु आयात एवं निर्यात संबंधी विनियमन”) में ये व्यवस्था है कि “राज्य वस्तुओं के मुक्त रूप से

आयात और निर्यात की अनुमति देगा, और कानून के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि आयात/निर्यात व्यापार उचित और व्यवस्थित ढंग से हो। उन वस्तुओं जिनका अयात एवं निर्यात करना किसी कानून या प्रशासनिक विनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्जित या प्रतिबंधित है, को छोड़कर कोई भी संगठन या व्यक्ति ऐसे उपायों को निर्धारित या लागू नहीं करेगा जिनसे वस्तुओं का आयात या निर्यात वर्जित या बाधित होता हो” इस संदर्भ में दहुआ ने प्रोटोकाल के अनुबंध 4 का उल्लेख किया है।

संबंधित उत्पाद और संबंधित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों चीन में कीमत नियंत्रण के अधीन नहीं है।

(क) प्राकृतिक गैस एवं भेषजीय उत्पादों जैसे चुनिंदा उत्पादों पर कीमत नियंत्रण अभी भी विद्यमान है। भेषजीय उत्पाद भारत सहित अनेक देशों में खास कर जीवन रक्षक औषधियों, सामान्य औषधियों आदि के बल्क नुस्खों के संबंध में कीमत नियंत्रण के अधीन हैं। इसी प्रकार, भारत ने हाल तक प्राकृतिक गैस को प्रशासनिक कीमत तंत्र के अधीन रखा था।

(ख) चीन में दड़ा गेहूँ जैसे कृषि उत्पाद सरकारी निर्देशन कीमत निर्धारण के अधीन हैं। यह न्यूनतम समर्थन कीमत और कृषि क्षेत्र में भारत में प्रचलित ऐसी वस्तुओं के आयात हेतु न्यूनतम कीमत के समान है। चीन में यूरिया सरकारी निर्देशन कीमत निर्धारण के अधीन है। भारत में यूरिया सरकारी खजाने से पर्याप्त सब्सिडी के साथ अभी भी प्रशासनिक कीमत निर्धारण के अधीन है।

(ग) भारत में भी गैस, जल, विद्युत जैसी सार्वजनिक उपयोगिताएँ कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर हाल तक सरकारी कीमत निर्धारण के अधीन रही थी किंतु निजी प्रतिस्पर्धियों के आने के कारण सरकारी कीमत तंत्र सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों अथवा सिंचाई विभाग, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य/संघ राज्य के जल बोर्ड, नगर निगमों, नदी धाटी प्राधिकरणों आदि जैसे सरकारी निगमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में समाप्त हो गया है। इस प्रकार के कीमत नियंत्रणों से भारत गैर-वाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं बनता है। इसी प्रकार, इन सार्वजनिक उपयोगिताओं में कीमत नियंत्रण का तात्पर्य यह नहीं होगा कि चीन गैर-वाजार अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहता है।

(घ) सेवा क्षेत्र में सरकारी कीमत तंत्र चीन में डाक एवं दूर संचार सेवाओं, पर्यटन स्थलों के लिए प्रवेश शुल्क, शिक्षा सेवाओं आदि के संबंध में विद्यमान है। यह कहना निर्धारक होगा कि भारत में भी ये सेवाएँ आज तक सरकारी कीमत तंत्र के अधीन हैं।

(ड) रेल भाड़ा और रेल यात्री किराया चीन में सरकारी निर्देशन कीमत तंत्र के अधीन है। भारत के मामले में ये स्वयं सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। रेल किराए को संसद द्वारा रेल बजट के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

इस प्रकार, चीन ने ऐसी कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छोड़ कर, जिन पर अनेक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों तथा पश्चिमी विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कीमत नियंत्रण बना हुआ है, लगभग सभी मदों पर कीमत नियंत्रण समाप्त कर दिया है।

प्रारंभिक जाँच परिणामों की अधिसूचना के पैरा 8.1.6 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दहुआ द्वारा प्रस्तुत व्यापार लाइसेंस एवं बैठक के कार्यवृत्त पर भी विचार किया था। दहुआ इस बात का पुनः उल्लेख करना चाहता है कि “राज्य के स्वामित्व” का तात्पर्य दहुआ के कारोबार में किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप से नहीं है। जैसा कि पर्याप्त साक्ष्य से सिद्ध हो गया है, धरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक बाजारी प्रतिस्पर्धी के रूप में दहुआ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और वह अपने लाभ एवं हानि के लिए जिम्मेवार है। दहुआ ने जाँच अवधि के दौरान हुई बैठक के बजाय यह कारण दर्शति हुए अपने पहले दावे में वर्ष 1997 की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रस्तुत की है कि यह वह बैठक थी जिसमें वर्तमान महाप्रबंधक श्री सु याओवी का चयन कर नियुक्त किया गया था। पहले दावे के अनुबंध 2 में यह उल्लेख किया गया था कि दहुआ के एक नए फैक्ट्री निर्देशक का चयन किया गया है। तथापि, पहले दावे में यथा उल्लिखित महाप्रबंधक और उसके अनुबंध में उल्लिखित फैक्ट्री निर्देशक के पद में कोई अंतर नहीं है। दोनों से ही दहुआ के प्रमुख श्री सु याओवी का संकेत मिलता है। दहुआ इस संबंध में जाँच अवधि में हुई बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ संबंधित पद के साक्ष्य सहित आगे और सूचना उपलब्ध कराना चाहेगा।

निर्यातक ने जाँच में सहयोग किया है तथा सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु निर्यातक की सूचना का सत्यापन किया गया है।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक को चीन जनवादी गणराज्य में गैर बाजार/बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के रूप में मानने के बारे में हितवद्ध पर्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की है। ऐसे व्यवहार को प्रासित करने वाले संगत नियम निम्नानुसार हैं:-

**15. सब्सिडी एवं पाटन के निर्धारण में कीमत तुलनीयता**

गैट 1994 के अनुच्छेद VI टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) और एस.सी.एम.करार डब्ल्यू टी ओ. सदस्य देश में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्रवाईयों में निम्नलिखित के अनुसरण में प्रयोग में लाए जाएं:-

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का प्रयोग करेंगे जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित नहीं होगी और निम्नलिखित नियमों पर आधारित हो:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के बारे में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था वाली स्थितियां मौजूद हैं तो आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग की चीन की कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेंगे।

(ii) आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित नहीं है। यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शता है कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के बारे में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां मौजूद हैं।

(ख) एस.सी.एम. करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्रवाईयों में अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग) और 14 (घ) में उल्लिखित इमदाद पर विचार करते समय एस.सी.एम. करार के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि यदि इस प्रयोग्यता में कोई विशेष कठिनाई आती है तो आयातकर्ता डब्ल्यू टी ओ सदस्य सब्सिडी लाभ को अभिज्ञात करने तथा उसकी मात्रा का पता लगाने के लिए ऐसी पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है जिनमें ऐसी संभावना को ध्यान में रखा जाता है जो चीन में विद्यमान नियंथनों एवं शर्तों के तहत उचित बेंचमार्क के रूप में हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियाँ लागू करते समय, जहाँ व्यवहार्य हो, आयातकर्ता डब्ल्यू टी ओ सदस्य को चीन से

बाहर प्रचलित निबंधनों एवं शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पूर्व इस प्रकार की प्रचलित निबंधनों एवं शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातकर्ता डब्ल्यू टी औ सदस्य पाटनरोधी पद्धति संबंधी समिति के उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयोग में लाई गई पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और वह समिक्षा एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के उपायों से संबंधित समिति के उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग में लाई गई पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) चीन द्वारा आयातकर्ता डब्ल्यू टी औ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक बार यह प्रमाणित कर दिए जाने के बाद कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, उप पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे बशर्ते कि आयातकर्ता सदस्य के राष्ट्रीय कानून में उक्त देश के शामिल होने की तारीख के अनुसार बाजार अर्थ-व्यवस्था संबंधी मानदंड निहित हों। उप पैरा (क)(ii) के प्रावधान शामिल होने की तारीख के बाद 15 वर्ष की समाप्ति पर हर हालत में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, यदि चीन आयातकर्ता डब्ल्यू टी औ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह सिद्ध कर देता है कि किसी उद्योग अथवा क्षेत्र विशेष में बाजार अर्थ व्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं तो उक्त उद्योग अथवा क्षेत्र पर उप पैरा (क) के गैर बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उपबंध आगे लागू नहीं होंगे।

#### मामले की शुरूआत के समय भारतीय कानून के अंतर्गत स्थिति

8. इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” शब्द से तात्पर्य ऐसे प्रत्येक देश से है जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी देश शामिल है जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो देश लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढाँचे के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे कि ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के उचित मूल्य का पता चल सके। ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या :-

(i) कच्ची सामग्रियों समेत कीमतों, लागतों और निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, निविष्टि बिक्रियां एवं निवेश के बारे में ऐसे देश की संबंधित फर्मों का निर्णय बाजारी संकेतों जो आपूर्ति एवं मांग प्रदर्शित करते हैं, के अनुसूच्य और इस बारे में पर्याप्त

सरकारी हस्तक्षेप के बिना लिया जाता है और क्या प्रमुख निविष्टियों से लागत के बाजार मूल्य पर्याप्ततः प्रदर्शित होते हैं,

- (ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है जो पूर्ण गैर - बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली खासकर परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के कारण आई हैं,
- (iii) ऐसी फर्मों दिवालीएप्न और सम्पत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं जो फर्म के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं, और
- (iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है ;

किन्तु रूस और चीन जनवादी गणराज्य की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट कारकों के बारे में लिखित में पर्याप्त साक्षों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी ही एक अथवा अधिक फर्मों के लिए विद्यमान बाजारी दशाएं पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 तक में निर्धारित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है।

टिप्पणी:- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चीन जनवादी गणराज्य, जॉर्जिया, कजाकस्तान, उत्तर कोर्त्या, किर्गिस्तान, मालदीव, मंगोलिया, रूस, ताजिकिस्तान, तुकमिनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान तथा वियतनाम शामिल हैं। इन देशों में से इस बात को सिद्ध करने वाला कोई देश कि वह इस पैराग्राफ में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, समस्त आवश्यक सूचना उपलब्ध करा सकता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत् विचार किया जाएगा।

#### 4 जनवरी 2001 के बाद भारतीय कानून के अंतर्गत स्थिति

8. (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” शब्द का अर्थ है कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं जिसके कारण ऐसे देश में पर्याप्त वस्तुओं की विक्रियाँ उप पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।

(2) यह कहना परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाठनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया अथवा माना गया है, एक गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश है।

तथापि गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:-

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य के हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;

(ख) ऐसे फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थ व्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती हैं। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के हास, अन्य राइट ऑफ, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्म दिवाला तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; तथा

(घ) विनिमय दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

तथापि, जहाँ इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जाँच के अधीन ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियाँ लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के बदले पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

दिनांक 4.1.2002 की अधिसूचना सं0 1/2002 एन.टी. सीमाशुल्क के द्वारा पैरा 8(1),(2) एवं (3) में संशोधन किया गया था।

दिनांक 10 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 101/2003 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध 1 के पैरा 8 में उप पैराग्राफ 3(घ) के बाद पैरा (4) जोड़ा गया था।

“(4) उपरोक्त उप पैराग्राफ (2) में कही हुई बातों के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का व्यवहार प्रदान कर सकते हैं यदि सार्वजनिक दस्तावेज में यथाउल्लिखित संगत मापदंडों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ हाल ही में डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य द्वारा उक्त देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया हो अथवा माना गया हो। इस संबंध में संगत मापदंडों में उपरोक्त उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड शामिल हैं।”

प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने अथवा सदस्य राज्य के लिए सविस्ती उपायों के प्रयोजनार्थ चीन के प्रति व्यवहार के लिए विकल्प दिए गए हैं।

- उपरोक्त संपूर्ण खंड के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि किसी डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य द्वारा चीन को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने अथवा चीन की कंपनियों या नियांतकों को आंशिक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने से रोका नहीं जा सकता है। वस्तुतः सदस्यों को चीन को समग्र रूप में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त है।

2. भारतीय कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि चीन में प्रचालनरत कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जा सकता है यदि वे नियमावली के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा करती हैं।
3. बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने वाले पक्षकार को उत्तरदायित्व देने के साथ ही भारतीय कानून में किसी कंपनी/सत्ता द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व के मापदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।
4. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार निर्यातकों ने चारों मापदंडों में से प्रत्येक के संबंध में विस्तृत अनुरोध उपलब्ध कराए थे जिन्हें प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था।
5. उपरोक्त के आलोक में चीन के सहयोगी निर्यातक, जिसने भारतीय कानून के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए मापदंडों को पूरा किया है, को बाजार अर्थव्यवस्था प्रदान करना और उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत को स्वीकार करना निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार में आता है और डब्ल्यूटीओ. के प्रति भारत की वचनबद्धता के संगत है।

प्राधिकारी ने उपरोक्त के आलोक में चीन जनवादी गणराज्य के सहयोगी निर्यातक की स्थिति की जाँच की है।

मै0 गुआंगसी दहुआ केमिकल फैक्ट्री, चीन (दहुआ) :

घरेलू बाजार में बिक्रियों, उत्पादन लागत तथा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावों के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने अपने निवेदन में यह स्वीकार किया था कि मै0 दहुआ एक राज्य स्वामित्व वाला उद्यम है जो औद्योगिक उद्यम तथा राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिक उद्यमों की प्रचालनात्मक व्यवस्था के रूपान्तरण के विनियम संबंधी चीन जनवादी गणराज्य के कानून द्वारा शासित होता है। बेज नगर सरकार, गुआंगसी प्रान्त उद्यम में एकमात्र शेयर धारक है।

तदनुसार, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि इस मामले में राज्य के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और इसलिए यह नियमावली के अंतर्गत दिए गए मापदंडों को पूरा नहीं करता है। इन कारणों से प्राधिकारी ने इस कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया है।

मै0 गुआंग्जी कैंग वु टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग कं0 लि0 (जी.सी.डब्ल्यू.टी.), मै0 गुआंग्सी जिंग मेई जियांग टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग कं0लि0 (जी.एक्स.एम.एक्स), मै0 झेजियांग प्रोविंसियल लाइट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी, हांगझोआउ, चीन (जेड.पी.एल.टी.) ।

डी जी ए डी द्वारा दोनों निर्यातकों की सूचना के साथ ट्रेडिंग हाउस जेड.पी.एल.टी. का सत्यापन किया गया है। जी.सी.डब्ल्यू.टी. के निर्यातकों ने विचारार्थ सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में पूरक सूचना प्रस्तुत की है। यद्यपि कंपनी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया गया है, तथापि बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे को प्रमाणित करने वाली कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। फरवरी 2004 के अपने फैक्स के द्वारा मै0 जेड.पी.एल.टी. ने बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया था। चूँकि जाँच समयबद्ध है अतः प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया है। सत्यापन दौरे के दौरान मै0 जी.एक्स.एम.एक्स पूरी तरह सहयोग करने में तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप एवं विधि से सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने अंतिम जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ सूचना को अस्वीकृत कर दिया।

#### मै0 जी.सी.डब्ल्यू.टी तथा मै0 जी.एक्स एम.एक्स.:

कंपनी ने निर्धारित प्रश्नावली में घेरेलू बाजार विकियों संबंधी सूचना प्रस्तुत की थी। चीनी उत्पादक ने सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र होने का दावा किया था और इसकी निजी स्थिति पर विचार करने पर वल दिया था। तथापि, बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति संबंधी सूचना न तो सत्यापन दौरे के पूर्व और न ही उसके दौरान प्रस्तुत की गई थी। सूचना 16.02.2004 को प्रस्तुत की गई थी परन्तु बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के उनके दावे संबंधी सत्यापन दौरे के बाद वह सत्यापित नहीं की जा सकती थी और इसलिए उसे अस्वीकृत कर दिया गया था।

### सामान्य मूल्य

#### मै0 गुआंगसी दहुआ केमिकल फैक्ट्री, चीन (दहुआ) :

प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने अपने निवेदनों में यह स्वीकार किया है कि वह एक राज्य स्वामित्व वाला उद्यम है। अंतिम जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में प्रस्तुत की गई सूचना/साक्ष्य नियमावली के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। प्राधिकारी ने विचार किया कि सामान्य मूल्य के आकलन के लिए नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए कई विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प को लागू किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विकल्प नियन्त्रित हैं :-

1. बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश की कीमत,
2. बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य,
3. किसी ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत,
4. भारत में वास्तविक रूप में भुगतान की गई कीमत जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया
5. भारत में वास्तव में भुगतान योग्य कीमत जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया

यह नोट किया गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य अथवा भारत में वास्तव में भुगतान योग्य कीमत, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो, वर्तमान मामले में सबसे उचित आधार हैं। वस्तुतः भारत जैसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत का परिणाम उच्चतर सामान्य मूल्य के रूप में होता। इसी के साथ यह भी संभव है कि ऐसी कीमतें वास्तविक एवं प्रतिनिधि कीमतों को नहीं दर्शाती हैं। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य को कच्ची सामग्री, उपयोगिताएं तथा क्षमता उपयोग के संबंध में उचित समायोजन करके भारत में सर्वाधिक कुशल उत्पादक की उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध सूचना को अंगीकृत करने के द्वारा परिकलित उत्पादन लागत पर आधारित किया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बिक्री लागत पर 5% के उचित लाभ पर विचार किया गया है। इस प्रकार, संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य \*\*\*\* डालर प्रति मी0 टन परिकलित होता है।

निर्यातक ने परिशिष्ट 4 में बिकी कीमत ढाँचे के साथ जाँच अवधि के दौरान भारत के निर्यात बिकियों के लिए सौदा-वार विवरण प्रस्तुत किया है। छूट/कमीशन (\*\*\* डालर), अंतर्रेशीय भाड़ा (\*\*\* डालर), कर (\*\*\* डालर), समुद्री भाड़ा (\*\*\* डालर) तथा बीमा (\*\*\* डालर) के लिए समायोजनों का दावा किया गया है और सत्यापन के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के उचित सत्यापन के बाद कारखाना द्वार स्तर पर \*\*\* डालर प्रति मी0 टन के रूप में निर्यात कीमत को अपनाया है।

मै0 कैंग वु शुनफेंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड कं0 लि�0, चीन (पूर्व नाम मै0 गुआंगजी कैंग वु टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग कं0 लि�0, चीन) ( जी.सी.डब्ल्यू.टी.)

### सामान्य मूल्य

कंपनी प्रश्नावली के उत्तर में घरेलू बाजार बिकियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की थी। सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया था कि कंपनी ने घरेलू बिक्र्याँ मै0 झेजियांग जियाकिसिंग ऑयल एंड पेट्रस फैक्ट्री, चीन तथा मै0 गुआंगझोउ हुआंगपू बाइहे पिंगमेंट कं0 लि�0, चीन के माध्यम से और निर्यात बिक्र्याँ मै झेजियाँग प्रोविंसियल एल एंड टी ग्रुप लाइट इंडस्ट्री कं0 लि�0, हांग झोउ (जेड.पी.एल.टी.) तथा मै0 गुआंगसी केमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के माध्यम से की थी। मै0 गुआंगसी केमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है, की स्थिति ज्ञात नहीं है चूंकि उन्होंने जाँच में सहयोग नहीं किया था। यद्यपि उत्पादक कंपनी अर्थात् कैंग वु ने सौदेवार घरेलू बिकियों का सारा विवरण प्रस्तुत किया है, तथापि यह नोट किया गया है कि घरेलू बिकी कार्यकलापों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना अपूर्ण तथा अपर्याप्त थी चूंकि खुदरा/वितरक व्यापारी के माध्यम से स्वतंत्र उपभोक्ता को घरेलू बिकियों के लिए बिकी की कड़ी प्रस्तुत नहीं की गई थी और सत्यापन के दौरान इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के बारे में कोई सूचना सत्यापन दौरे के पूर्व अथवा उसके दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी। सत्यापन दौरे के पश्चात् बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के उनके दावे के संबंध में 16.02.2004 को प्रस्तुत की गई सूचना सत्यापन योग्य नहीं थी और अतः उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य को कच्ची सामग्री, उपयोगिताएँ तथा क्षमता उपयोग के संबंध में उचित समायोजन करके भारत में सर्वाधिक कुशल उत्पादक की उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध सूचना

को अंगीकृत करने के द्वारा परिकलित उत्पादन लागत पर आधारित किया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बिक्की लागत पर 5 प्रतिशत के उचित लाभ पर विचार किया गया है। इस प्रकार, संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य \*\*\* डालर प्रति मीट्रिक टन परिकलित होता है।

### निर्यात कीमत

निर्यातक ने परिशिष्ट 4 में बिक्की कीमत ढाँचे के साथ जाँच अवधि के लिए भारत को निर्यात बिक्रियों के लिए सौदेवार विवरण प्रस्तुत किया है। चूँकि निर्यात बिक्रियाँ मै0 डेजियांग प्रोविंसियल एल एंड टी ग्रुप लाइट इंडस्ट्री कं0 लि�0, हॉंग कॉउ (जैड पी एल टी) के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, अतः प्राधिकारी ने कारखाना - द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए अंतर्रेशीय भाड़ा (\*\*\* डालर), कर (\*\*\* डालर), समुद्री भाड़ा (\*\*\* डालर) तथा बीमा (\*\*\* डालर) के लिए समायोजन पर विचार किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का उचित सत्यापन करने के पश्चात् कारखाना द्वारा स्तर पर संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत \*\*\* डालर प्रति मीट्रिक टन के रूप में अपनाई है। जहाँ तक मै0 गुआंगसी केमिकल इंपौर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, जिसने जाँच में सहयोग नहीं किया, के माध्यम से की गई बिक्की की मात्राओं का संबंध है, उन्हें अवशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

### गुआंगसी जिंग मेंडे जियांग टाइटेनियम मैन्यूफैक्चरिंग कं0 लि�0 (जी.एक्स.एम.एक्स)

सत्यापन दौरे के दौरन उत्पादक कंपनी ने उत्पादन लागत, घरेलू बिक्रियों, अन्य देशों को बिक्रियों, समायोजन, निर्यात कीमत, लेखा परीक्षा खाते आदि के विषय में संगत सूचना सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की थी। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने कंपनी को असहयोगी माना है और निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। कंपनी को अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा।

### मै0 शाओगुआन केमिकल प्लांट, चीन

प्रारंभिक जाँच परिणाम में प्राधिकारी ने नोट किया था कि निर्यातक द्वारा दिया गया निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर कई प्रकार से त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त है :-

1. प्रश्नावली के सामान्य विवरणात्मक भाग (प्रश्नावली का क से ज भाग) का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
2. परिशिष्ट 7 उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. परिशिष्ट 3 में दी गई माहवार बिक्रियाँ जाँच अवधि के सभी महीनों के लिए नहीं दी गई प्रतीत होती हैं।
4. परिशिष्ट 1 में दी गई सौदेवार बिक्रियों में घरेलू बाजार में सभी बिक्रियाँ शामिल प्रतीत नहीं होती हैं।
5. पिछले दो वर्षों और जाँच अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. इस बात का कोई दावा नहीं किया गया है कि कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी का व्यवहार प्रदान किया जा सकता है।

प्रारंभिक जाँच परिणामों के पश्चात कोई उत्तर नहीं दिया गया है और निर्यातक को असहयोगी निर्यातक माना गया है और निर्यातक के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। कंपनी अवशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आएगी।

#### मै0 मानशान केमिकल (गुप) कं0 लि0 चीन

भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने निर्यातक से प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत किया है तथा याचिका की गैर गोपनीय पाठ एकत्रित किया है ताकि निर्यातकों के प्रश्नावली को प्रस्तुत किया जा सके तथापि, कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी ने जाँच के प्रयोजनार्थ निर्यातक को असहयोगी निर्यातक माना है।

#### जियाओजुओ जनरल केमिकल प्लांट, चीन

निर्यातक ने कहा है कि उनका संयंत्र राज्य के स्वामित्ववाला व्यापक अकार्बनिक रसायनिक संयंत्र है जिसकी चार शाखा कंपनियाँ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि संबद्ध सामग्री को चीनी सीमा शुल्क में एचएस कोड 32061110 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इनका याचिका में सूचीबद्ध आयातकों से कोई भी व्यावसायिक संबंध नहीं है। इन्होंने सीमा शुल्क आंकड़ा चार्ट से अपने दावे के

समर्थन में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। ऐसी परिस्थिति में, प्राधिकारी ने निर्यातक को जाँच के प्रयोजनार्थ असहयोगी निर्यातक माना है।

ऐनजिहुआ आयरन एंड स्टील ग्रुप कॉरपोरेशन, चीन

भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने कहा है कि निर्यातक जाँच में सहयोग देने के इच्छुक हैं। तथापि, कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में प्राधिकारी ने निर्यातक को जाँच के प्रयोजनार्थ असहयोगी निर्यातक माना है।

मुआंगसी बाइहि इंडस्ट्री कं0 लि0, चीन

निर्यातकों ने समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि प्रश्नावली का जवाब दिया जा सके। जिसे प्राधिकारी ने मान लिया तथा समय को 17.03.2003 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी। तथापि कोई भी जवाब फाइल नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में जाँच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने निर्यातक को असहयोगी निर्यातक मान लिया।

असहयोगी निर्यातकों के लिए :

प्राधिकारी ने सभी असहयोगी निर्यातकों के संबंध में कच्ची सामग्री, उपयोगिताओं और क्षमता उपयोग के संबंध में समुचित समायोजन करके भारत में सबसे कुशल उत्पादक की उत्पादन लागत से संबंधित उपलब्ध सूचना को अंगीकार करके उत्पादन की परिकलित लागत को सामान्य मूल्य का आधार माना है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बिक्रियों की लागत पर 5 प्रतिशत के उचित लाभ पर विचार किया गया है। अतः संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य (\*\*\* ) डालर प्रति मी0 टन बनता है। जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, इसके लिए जाँच में किसी सहयोगी निर्यातक के निम्नतम निर्यात कीमत सौदा (\*\*\* ) डालर को आधार बनाया गया है क्योंकि नियम 6(8) के अनुसार यह प्राधिकारी के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना थी।

### पाटन मार्जिन

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

“डंपिंग का मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासम्भव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी, अंतर में शामिल है: बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किये जाते हैं।

प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरा भारित औसत कारखाना द्वार पर निर्यात मूल्य तथा भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना की है ताकि संबद्ध देशों के सभी निर्यातक/उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन निकाला जा सके।

इस प्रकार आकलन किया गया पाटन मार्जिन काफी अधिक है और नियमों के तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से अधि है। संबद्ध देश की संबद्ध वस्तु के निर्यातक/ उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	निर्यातक / उत्पादक	सामान्य मूल्य (डॉलर/मी. टन)	कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत (डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन डॉलर/मी. टन	निर्यात कीमत के % के रूप में पाटन मार्जिन
1.	मै0 गुआंगसी दहुआ कैमिकल फैक्ट्री, चीन जनवादी गणराज्य (दहुआ)	***	***	***	23.9%
2.	मै0 कांग वु शुन फेंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड कं0 लि0, चीन पी0आर0 के मै0 झीजियांग प्रेविनशियल लाइट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी, (जेड.पी.एल.टी.) हांगझोउ, चीन जन0गण10 के माध्यम से निर्यात	***	***	***	26.9%
3.	अन्य सभी निर्यातक	***	***	***	27.9%

### (झ.) क्षति और कारणात्मक संबंध

9.0 क्षति के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों में यह उल्लेख है कि:

I. क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी।

II. पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के संबंध में, जैसा कि नियम 19 के उप-नियम (2) में उल्लेख है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना है अथवा उस कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के अनुबंध II(iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि जैसे ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने निवल बिक्री प्राप्ति और उत्पादन लागत को समायोजित कर लिया है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि इसे कुछेक मापदंडों (उत्पादन लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकदी प्रवाह, निवेश पर आय) के संबंध में प्रकटन विवरण में उचित ढंग से प्रदर्शित किया गया प्रतीत नहीं होता है।

## 9.1 आयातों की मात्रा एवं बाजार हिस्सा:

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जांच अवधि (जनवरी,02-दिसंबर, 02)
आयात (मी.टन)				
चीन जन.गणराज्य	359	1069	1543	6362*
अन्य देश	2894	2177	2622	2192*
कुल आयात	3253	3246	4165	8554
घेरलू उद्योग की विक्रियाँ	17286	17011	14921	12265
अन्य उत्पादक	3739	3920	4972	5966
कुल मांग	24278	24177	24058	26785
आयातों का हिस्सा				
चीन जन.गणराज्य का हिस्सा	11%	33%	37%	74%
अन्य का हिस्सा	89%	67%	63%	26%
कुल	100%	100%	100%	100%
मांग में हिस्सा				
चीन जन.गणराज्य	1%	4%	6%	24%
अन्य देश	12%	9%	11%	8%
घेरलू उद्योग	71%	70%	62%	46%
अन्य उत्पादक	15%	16%	21%	22%
कुल	100%	100%	100%	100%
भारत में उत्पादन के संबंध में आयात	2%	6%	10%	49%

आँकड़ों में डी जी सी आई एस द्वारा अध्याय 28 के अंतर्गत बताए गए आयात एवं आई वी आई एस, मुम्बई और डी जी सी आई एस द्वारा जांच अवधि के लिए अध्याय 32 के अंतर्गत बताए गए सौदेवार व्यौरे शामिल हैं। विभिन्न देशों से हुए आयात, आयातों और भारत में मांग के अनुसार उनके हिस्से को उपर दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह बताया गया है कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा आयातों को अन्य सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके समर्थन में उन्होंने निर्यात आँकड़ों संबंधी सूचना, जिसे चीनी सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने का दावा किया गया है, और गौण स्रोतों से सौदेवार आँकड़ों को प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता

ने अन्य उत्पादों के संबंध में डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात आंकड़ों संबंधी व्यौरे भी प्रस्तुत किये हैं और उन व्यौरे में संबद्ध वस्तु के आयातों को दर्शाया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा बताए गए आयात आंकड़े इस जांच में सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात आंकड़ों से लगभग 30 प्रतिशत कम हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह निवेदन किया गया है कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा अध्याय 28 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई संबद्ध वस्तु के आयात अपूर्ण हैं। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि आयातों को अध्याय शीर्ष 3206 (माइका पिगमेन्ट्स) के अंतर्गत भी रिपोर्ट किया गया है। डी जी सी आई एंड एस और आई बी आई एस, मुम्बई द्वारा उपशीर्ष 3206 (माइका पिगमेन्ट्स) के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का एक सौदेवार विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण में यह दर्शाया गया है कि टाइटेनियम डायऑक्साइड (एनाटेस) की जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा चीन जन० गणराज्य से 6000 मी०टन से अधिक और अन्य देशों के मामले में 2000 मी०टन से अधिक थी। प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु के कुल आयात जांच अवधि के दौरान 3087 मी०टन बनते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनेक वास्तविक निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि :-

- (क) चीन से आयात समग्र रूप से बढ़े हैं,
- (ख) भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है,
- (ग) भारत में संबद्ध माल की मांग की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है। साथ ही, घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आयी है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में उत्पादन एवं खपत दोनों की तुलना में पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आयातों में स्पष्ट रूप से प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव प्रदर्शित होता है। यह प्रतिकूल प्रभाव पर्याप्त एवं वास्तविक है।

घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया था कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों से कीमतों में अन्यथा कमी हुई है अथवा पर्याप्त मात्रा में कीमतों में वृद्धि होने से रुकावट आई है जिससे अन्यथा रुकावट आ गयी होती। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन से पाटित आयातों की भारित

अन्यथा रुकावट आ गयी होती। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन से पाटित आयातों की भारित औसत उत्तराई मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्की वसूली के साथ की थी। प्राधिकारी ने 1 प्रतिशत उत्तराई प्रभार और सी आई एफ आयात कीमत में लागू मूल सीमा शुल्क जोड़कर आयातों की उत्तराई मूल्य की गणना की है। घरेलू उद्योग की औसत बिक्की वसूली के निर्धारण में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गयी छूट, कमी और कमीशन और भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को अलग रखा है। यह पाया गया था कि चीन से हुए आयातों से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त रूप से कटौती हुई है। सहयोगी निर्यातकों और असहयोगी निर्यातकों के लिए कटौती की समीक्षा का निर्धारण पृथक रूप से किया गया था। सहयोगी निर्यातकों के लिए कटौती का प्रतिशत अधिक पाया गया था।

जहां तक आयात मात्रा में परिवर्तन का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकार्कर्ता द्वारा गौण स्रोतों से आयातों की सौदेवार विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई गई थी जिससे (क) अध्याय 32 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक आयातों और (ख) विचाराधीन उत्पाद कते लिए वर्गीकरण के तहत सूचित रुटाइल ग्रेड के आयातों का पता चलता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उपलब्ध की गई सौदेवार आयात सूचना को डी जी सी आई एंड एस के पास भेजा और यह पाया गया कि अध्याय 32 के अंतर्गत आयात याचिकार्कर्ता द्वारा दावा किए गए आयातों से वस्तुतः काफी अधिक थे। वास्तव में यह पाया था कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई मात्रा से काफी अधिक थी। अतः प्राधिकारी आयात मात्रा को संशोधित करना और उसे ठीक करना उचित समझते हैं।

जहां तक लिखित अनुरोधों के बाद घरेलू उद्योग द्वारा दायर सूचना उपलब्ध न किए जाने के आरोप का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था जिसे सार्वजनिक फाइल में रखा गया था। वस्तुतः दाहुआ ने भी लिखित अनुरोधों के बाद पर्याप्त सूचना दायर की थी।

जहां तक आयात मात्रा के संभावित दोहरे लेखाकरण का संबंध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रकटन विवरण में अलग-अलग स्रोतों से उपलब्ध कराए गए आकड़ों में अलग-अलग अध्याय के तहत अलग-अलग अवधियों और आयातों का पता चलता है। अतः दोहरे लेखाकरण की संभावना नहीं बन सकती।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां एक हितबद्ध पार्टी ने मांग में कमी का पहले आरोप लगाया था वहीं दूसरी हितबद्ध पार्टी ने अब मांग में पर्याप्त वृद्धि का आरोप लगाया है और उसे 22500 मी० टन (अनुमानित और असत्यापनीय दावा) होना प्रदर्शित किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान प्रमाणित अधिकतम मांग 26785 मी० टन रही थी जबकि देश में सृजित क्षमता 28100 मी० टन की है।

## 9.2 घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मापदंड

क्षति विश्लेषण केवल मैसर्स टी टी पी एल और कोलमेक से संबंधित है, जो भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है एवं घरेलू उद्योग का गठन करता है। घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित विभिन्न मापदंड निम्नानुसार हैं:-

## 1. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियाँ

घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियाँ निम्नानुसार हैं:-

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
क्षमता	28100	28100	28100	28100
उत्पादन	17511	16891	15774	12892
क्षमता उपयोग	62%	60%	56%	46%
बिक्रियाँ की मात्रा	17286	17011	14921	12265
बिक्रियाँ का मूल्य (सूचीबद्ध)	100.00	102.37	88.79	70.38

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि:-

(क) घरेलू उद्योग की संबद्ध माल की क्षमता क्षति की अवधि में अपरिवर्तित रही। तथापि, क्षति अवधि में उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में पर्याप्त गिरावट आयी,

(ख) बिक्री की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है। साथ ही आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ग) घरेलू उद्योग में बिक्री में आगे भी हानि हो सकती है क्योंकि कीमतों में कमी होने के बावजूद, आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही है।

## 2. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

(सूचीबद्ध)	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
निवल बिक्री वसूली	100.00	104.67	102.43	90.00
उत्पादन लागत	100.00	103.91	107.39	109.80
उत्पादन की इष्टतम लागत				****

(क) घरेलू उद्योग कीमतों में कमी से जूझ रहा है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि घरेलू उद्योग को कीमतों कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कीमत कटौती 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की सीमा में है।

(ख) घरेलू उद्योग की कीमतों कम हो रही हैं।

(ग) उत्पादन की इकाई लागत में जो वृद्धि हुई थी उसका प्रमुख कारण क्षमता उपयोग में गिरावट का आना था और परिणाम स्वरूप ऊपरी लागतों में वृद्धि हुई थी। तथापि, यह पाया गया था कि निवल बिक्री वसूली उत्पादन की इष्टतम लागत से कम थी। यह बात भी नोट की जाती है कि क्षमता उपयोग में गिरावट बाजार में पाठित आयातों के फलस्वरूप बिक्री मात्रा में गिरावट आने के

कारण हुई थी। इस प्रकार, उत्पादन की इकाई लागत में जो वृद्धि हुई है वह चीन से पाटित आयातों के फलस्वरूप हुई है।

(घ) घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में कटौती के बावजूद आयातों के फलस्वरूप कम कीमत पर बिकी हो रही है।

(ङ) संबद्ध देश से आयातों का पहुँच मूल्य नुकसान रहित कीमत से कम है। इस प्रकार आयातों के फलस्वरूप बाजार में कम कीमतों पर बिकी हो रही है। कम कीमत पर जो बिकी हो रही है वह 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की सीमा में है।

जहां तक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिकी के समान स्तर का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निवल बिक्री प्राप्ति से अधक है। अतः यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें क्षतिरहित कीमत और निवल बिक्री प्राप्ति काफी मिलती-जुलती है। किसी भी हालत में घरेलू उद्योग को हुई क्षति तब प्रमाणित होती है जब आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति तथा क्षतिरहित कीमत दोनों से कम हो और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति क्षतिरहित कीमत से कम हो, जो इस मामले की वास्तविकता है।

### 3. रोजगार एवं मजदूरी

इन वर्षों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आयी है। घरेलू उद्योग द्वारा देय मजदूरी में कमी आयी है। तथापि, मजदूरी में कमी आने के बावजूद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

### 4. उत्पादकता

संबद्ध माल की उत्पादकता एवं बिकियों से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का विश्लेषण करने की दृष्टि से प्राधिकारी ने उत्पादन की इकाई लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि की जांच की थी। संगत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सूचीबद्ध	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
ठकाई निवल बिक्री वसूली	100.00	104.67	102.43	100.90
उत्पादन की इकाई लागत	100.00	103.91	107.39	109.80

कोष्ठक में अंकड़े हानि दर्शते हैं।

### 5. वस्तुसूची

उत्पादन में कमी होने के बावजूद घरेलू उद्योग को बढ़ते वस्तुसूची स्तर का सामना करना पड़ रहा है। औसत दिनों में स्टॉक में उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ा है। वस्तुतः सत्यापन के समय प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि घरेलू उद्योग को स्टॉक करने तथा बढ़ते वस्तुसूची को बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वस्तुसूचियों का औसत स्तर अभूतपूर्व प्रतीत होता था, जैसाकि नीचे की सारणी में देखा जा सकता है :-

मीटन	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
	1042	1143	1560	3132

### 6. नकद प्रवाह

जबकि कंपनी को संबद्ध वस्तु की बिक्री तथा उत्पादन से सकारात्मक नकद प्रवाह हो रहा था, घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक हानि के कारण नकद प्रवाह जाँच अवधि में नकारात्मक हो गया। जैसा कि नकद प्रवाह संबंधी सूचना के बारे में नीचे की सारणी से स्पष्ट है :-

सूचीबद्ध	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
नकद प्रवाह	100.00	100.94	55.61	8.28

(कोष्ठक में आंकड़े नकद हानि दर्शाते हैं)

### 7. उत्पादकता

प्रति कर्मचारी उत्पादन और प्रतिदिन उत्पादन के अनुसार, कर्मचारियों की संख्या में कमी आने के बावजूद उत्पादन के उच्चतम स्तर के तहत घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी आई है।

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
उत्पादन प्रतिदिन	48	46	43	35
उत्पादन प्रति कर्मचारी	21.73	21.58	22.41	19.03

### 8. वृद्धि

उत्पादन की मांग में वृद्धि होने तथा सकारात्मक होने के बावजूद, पाटित आयात के कारण कंपनी की वृद्धि नकारात्मक रही है। जैसा कि बिक्री मात्रा में गिरावट, मांग में वृद्धि और भारत में खपत में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट से देखा जा सकता है।

### 9. बाजार हिस्सा

चीन, अन्य देशों, घरेलू उद्योग और भारत में खपत में अन्य भारतीय उत्पादकों के आयातों का हिस्सा निम्नानुसार रहा है :-

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
मांग में हिस्सा				
चीन जन.गणराज्य	1%	4%	6%	24%
अन्य देश	12%	9%	11%	8%
घरेलू उद्योग	71%	70%	62%	46%
अन्य उत्पादक	15%	16%	21%	22%
कुल	100%	100%	100%	100%

उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि:-

- (क) भारत में चीन से होने वाले आयतों की खपत के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- (ख) खपत में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आयी है।
- (ग) अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादक (मैसर्स किलबर्न कैमिकल्स) के प्रकाशित वित्तीय परिणामों से यह पाया गया था कि इस कंपनी को कीमत कटौती का सामना करना पड़ रहा है और इस अवधि में इसकी लाभप्रदता में कमी आयी है।

#### 10. निवेशों पर आय

घरेलू उद्योग के लाभ में पर्याप्त गिरावट आने से सीधे निवेशों पर आय में गिरावट आयी। इसके अलावा, यद्यपि निवेशों पर आय पहले सकारात्मक थी तथापि क्षति की अवधि में यह नकारात्मक रही, जैसाकि नीचे की सारणी में देखा जा सकेगा:-

सूचीबद्ध	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जाँच अवधि
निवेश पर आय	100.00	95.46	40.49	(6.75)

#### 10. नये निवेश बढ़ाने की क्षमता -

घरेलू उद्योग को नए निवेश की योजना बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि निष्पादन में अत्यधिक कमी आई है।

9.3 हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग को क्षति बिक्रीकर के उच्च प्रभाव के कारण हुई है जिसे मैसर्स टी टी पी एल ने वहन किया है। अगे यह भी तर्क दिया गया कि अन्य भारतीय उत्पादकों के निष्पादन में कमी नहीं आई है। इस संबंध में प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि :

I) प्राधिकारी क्षतिरहित कीमत का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर करते हैं। ऐसी स्थिति में, कारखाना द्वार से बाहर उत्तर बिक्री खर्च, करों, शुल्कों का कोई भी प्रभाव पाटित आयतों पर नहीं पड़ा है।

II) अन्य भारतीय उत्पादकों के निष्पादन में भी कमी आई है। मैसर्स कॉलमेक ने तब से लागत संबंधी जानकारी एवं क्षति की जानकारी दी है, जिसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है। यह देखा जाता है कि कॉलमेक के निष्पादन में भी वास्तविक कमी आई है। यद्यपि किलबर्न कैमिकल्स ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है, तथापि वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही रिपोर्ट से यह पाया गया है कि इस कंपनी को कीमतों में अत्यधिक कटौती करनी पड़ रही थी और इसकी लाभप्रदता में वास्तविक कमी हो रही थी।

III) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उक्त तर्क क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के लिए प्रासंगिक हो सकता है ! जहां तक घरेलू उद्योग की क्षति पर बिक्री कर के प्रभाव का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3 और नियमों के अनुबंध 2 के तहत घरेलू उद्योग की क्षति के बारे में अनेक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की जांच करने की अपेक्षा की गई है। इन मापदंडों में सुधार अथवा कमी के कारणों की जांच क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित नहीं हैं। जहां तक कारणात्मक संबंध की दृष्टि से बिक्री कर के प्रभाव का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) प्राधिकारी ने बिक्री कर को छोड़ने के बाद क्षतिरहित कीमत के निर्धारण सहित क्षति का पूर्ण विश्लेषण किया है। (ख) अन्य भारतीय उत्पादकों की लाभप्रदता में भी कमी आई है। यद्यपि कोलमेक की सत्यापित सूचना से यह पता चलता है कि कंपनी के निष्पादन में भी पर्याप्त कमी आई है तथापि वार्षिक रिपोर्टों और तिमाही रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जांच अवधि में कंपनी द्वारा संदर्भ बिक्री कर 8% था न कि 30% जैसा कि किसी पार्टी ने आरोप लगाया है। 30% बिक्री कर की सामान्य दर थी जबकि कंपनी की बिक्री कर की काफी रियायती दर मंजूर की गई थी। जहां तक बिक्री कर की समाप्ति के कारण तेजी से बिक्री करने कि घरेलू उद्योग की क्षमता का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति प्राधिकारी द्वारा आकलित क्षति से काफी अधिक थी। पाटनरोधी शुल्क लगभग उसी समय लगाया गया था। अतः प्रासंगिक नहीं है कि घरेलू उद्योग अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और/अथवा बिक्री कर की समाप्ति के कारण बिक्री कर सका है।

## 10.0 कारणात्मक संबंध

1. अन्य देशों से आयात की मात्रा तथा मूल्य या तो न्यूनतम है या कीमतें अत्यधिक हैं, जैसा कि अन्य देशों से हुए आयातों संबंधी सूचना से देखा जा सकता है।
2. उत्पाद की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

1999-2000	24278
2000-2001	24177
2001-2002	24058
2002-2003	26785

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि डी जी सी आई एंड एस में दी गयी सूचना के अनुसार जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के आयातों में समग्र आयात के ब्यौरे परिकलित नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध माल के आयात की सूचना वर्गीकरण 3206 में दी जा रही है। इस दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता ने गौण श्रोतों के अनुसार आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जिनमें 3206 के तहत पर्याप्त आयात दर्शाया गया है। प्राधिकारी ने 3206 के लिए उपलब्ध डी.जी.सी.आई.एंड.एस की विस्तृत सौदेवार आयात संबंधी सूचना की जांच की थी और उसमें यह पाया था कि आयातों की पर्याप्त मात्रा (5735 एम.टी.) की सूचना केवल 3206 के तहत दी गयी है।

वस्तुतः सहयोगी निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात डी जी सी आई एंड एस द्वारा सूचित आयातों से अत्यधिक हैं। अतः मांग में संभव गिरावट से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

4. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होता है :-

(क) चीन से हुए आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से कम थी, जिससे घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने पर बाध्य होना पड़ा है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत कम करने को बाध्य हुआ है और जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटों और नकद घाटों की स्थिति उत्पन्न हुई जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में लाभ और धनात्मक नकदी प्रवाह की स्थिति थी।

(ख) चीन से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कमी हुई है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप यद्यपि घरेलू उद्योग की वस्तु सूची में वृद्धि हुई है तथापि उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में नुकसान हुआ है।

(ग) यद्यपि आयातों की मात्रा और उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी।

(घ) चीन से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के कारण चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई थी। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है।

(इ) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम होने से निवेश पर आय की स्थिति बिगड़ी है।

(च) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन खराब हुआ है और पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

(ज) भारतीय उद्योग का हित:

11.1 सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः लाना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

11.2 प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रुकेगा और संबद्ध उत्पादों के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होंगे।

11.3 प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होंगे और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के एक से अधिक स्रोत रख सकते हैं।

#### ट. निष्कर्ष :

12. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :-

- (i) भारत को चीन से टिटेनियम डाइआक्साइड का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।
- (ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे आगे और क्षति होने की आशंका है।
- (iii) यह क्षति समग्र रूप से संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण हुई है।

13. प्राधिकारी संबद्ध देशों से टिटेनियम डाइआक्साइड के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं ताकि घेरलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन, मार्जिन उपर्युक्त पैराग्राफों दर्शाया गया है। प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या इससे कम के पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया जाएगा तो उससे घेरलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की भारित औसत क्षतिरहित बिकी कीमत के साथ की गई है।

14. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि उपर्युक्त पैरा में किए गए अवलोकनों के अधीन अंतिम निर्धारण होने तक संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 या किसी अन्य अध्याय के अंतर्गत आने वाले टिटेनियम डाइआक्साइड एनाटेस के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तारीख से निम्नानुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। पाटनरोधी शुल्क निम्नांकित तालिका के कॉलम(9) में उल्लिखित राशि तथा प्रति किग्रा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा जिसे संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर लगाया जाए।

क्रम संख्या	सीमांशुलक उपशीर्ष संदर्भ	बस्तुओं का विवरण	विविहित उदगम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. 28 23 अथवा 32 06	टाइटेनियम डायऑक्साइड	एनोटेज चीन जन. गण.	कोई भी देश	मे. गौणवस्त्री बहुआ कैमिकल फैक्टरी, चीन जन. गण.,	कोई भी निर्यातक	1227.00	प्रति मी.टन	अमेरिकी डॉलर	
2. 28 23 अथवा 32 06	टाइटेनियम डायऑक्साइड	एनोटेज चीन जन. गण.	कोई भी देश	मे. कंग दू शुन फैग डायटेनियम डायऑक्साइड के लि., चीन जन. गण.	डोजियांग मे. डोजियांग डायटेनियम डायऑक्साइड एंड ट्रेक्सटाइल इंडस्ट्री, होंगजां, चीन जन. गण.	1227.00	प्रति मी.टन	अमेरिकी डॉलर	
3. 28 23 अथवा 32 06	टाइटेनियम डायऑक्साइड	एनोटेज चीन जन. गण.	कोई अतिरिक्त अन्य देश	मे. गुआंगजी बहुआ कैमिकल फैक्टरी, चीन जन. गण., कंग दू शुन फैग डायटेनियम डायऑक्साइड के लि., चीन जन. गण., के अतिरिक्त कोई अन्य निर्यातक	कोई भी निर्यातक	1227.00	प्रति मी.टन	अमेरिकी डॉलर	

17. उपर्युक्त के अधीन, प्राधिकारी 5 अप्रैल, 2002 के प्रारंभिक जांच घटियों की पुष्टि करते हैं।
18. प्राधिकारी, उपर्युक्त अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार निश्चयात्मक उपाय, जैसा कि इसमें सिफारिश की गई है को जारी रखने, इसमें संशोधन करने अथवा समाप्त करने संबंधी जरूरतों की समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी समीक्षा का कोई अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के अन्दर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर न किया जाए।
19. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील संबंधित अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2004

**Final Findings**

**Subject :** Anti-dumping investigation concerning import of Titanium Dioxide originating in or exported from People's Republic of China.

No. 14/51/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

**A. PROCEDURE**

- 1.0 The procedure described below has been followed with regard to the investigation:-
- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from Titanium Dioxide Manufacturer's Association (hereinafter referred to as petitioner) on

behalf of the domestic industry, alleging dumping of Titanium Dioxide (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country);

- (ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.
- (iii) The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
- (iv) The Authority issued a Public Notice dated 16<sup>th</sup> January, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Titanium Dioxide originating in or exported from People's Republic of China, classified under heading 28.23.00 and 28.23.00.01 under Indian Trade Classification of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975;
- (v) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters (whose details were made available by petitioner), importers (whose details were made available by petitioner), chambers of commerce and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2);
- (vi) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassy of subject country in India. A copy of the non-confidential petition was also provided to other interested parties, wherever requested.
- (vii) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to all known exporters/ producers, in accordance with the Rule 6(4). Response/ information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/ producers before preliminary findings:-
  1. M/s. Guangxi Dahua Chemical Factory ,China
  2. M/s Guang Xi Xing Mei Xiang Titanium Dioxide Co Ltd, China;
  3. M/s Guang Cang Wu Titanium Manufacturing Co Ltd, China;
  4. M/s Shaugan Chemical plant , China;
- (viii) The Embassy of China in New Delhi was also informed about the initiation of investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the known exporters was also sent to the Embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3).

(ix) The questionnaire was sent to ; to all known importers/users of the subject goods in accordance with Rule 6(4): Response/ information to the questionnaire/ notification was filed by the following importers/ users:

1. M/s Snowcem India Ltd. Mumbai;
2. M/s Bhimrajk Impex LTD, Mumbai;
3. M/s Chemi Enterprise , Mumbai
4. M/s Nerolac Paints
5. M/s.Berger Paints
6. EASTCORP International, Kolkatta

The exporters / importers sought extension of time for furnishing of reply to the questionnaire. The Authority considered the request and allowed extension of time of ten days to two weeks for submission of reply by the interested parties.

- (x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- (xi) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 6<sup>th</sup> June,2003 and requested the interested parties to make their views known in writing within 40 days from the date of its publication.
- (xii) Authority held a oral hearing on 8<sup>th</sup> August,03. The interested parties who attended the hearing were requested to submit their written submission as per schedule.
- (xiii) \*\*\* in this notification represents information furnished by the interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xiv) The Authority sought and verified information given by the domestic industry and to this end investigations were carried out at the premises of the petitioners at TTPL, Kerala, and supporter M/s Kolmac, Chemicals, Kolkatta
- (xv) The Authority also conducted cost investigation and worked out optimum cost of production and cost to make and sell subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.
- (xvi) Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> January, 2002 to 31<sup>st</sup> December 2002 i.e. the period of investigation (POI).
- (xvii) Additional details regarding injury were sought from the petitioner, which were also furnished.

- (xviii) The Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry as well as cooperative exporters to the extent considered necessary.
- (xix) Central Government vide OM No. 354/51/2003 TRU dated 9.1.2004 granted two month extension from 16.1.2004 for completing the investigation.
- (xx) In accordance with Rule 16 of the Rule supra, the essential facts /basis considered for these findings are being disclosed to known interested parties and comments received on the same would be duly considered in the final findings.

**B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY:**

**2.0 VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:**

- a) They have stated that though there are many exporters of subject goods from China, only few exporters have filed a written submission. Absence of other exporters or their representatives in oral hearing seemingly reflects the lack of interest of these exporters in the investigation.
- b) They have stated that decision of Designated Authority with respect to rejection of market economy treatment (MET) for M/s. Dauha in the preliminary findings is in accordance with the legal provisions.
- c) Petitioners have submitted that the exporter should provide sufficient information in the non-confidential version of the response.
- d) The petitioners have reiterated that the imports from China are in fact undercutting the price of petitioner company in the Indian market indicating that the imports were causing injury to the domestic industry in the investigation period.
- e) Petitioners have stated that China has exported both rutile and anatase grade of the material. The imports have been reported in several customs classifications including under "2823". These imports seem to have been included and reported under anatase category as reported in DGCI&S statistics considering that 8 digit classification has not been mentioned. Petitioner has provided detailed transaction wise listing of imports as per secondary sources to establish that very significant volumes is being reported under customs heading 3206. As per the IBIS data provided by the petitioner, significant volume of imports from China in these IBIS statistics have been reported under customs heading 3206.
- f) Imports from China are in fact undercutting the prices of the domestic industry. Argument of the exporter is based on average export price as per DGCI&S, which is incorrect due to (a) inclusion of rutile grade in

classification meant for anatese grade; (b) reporting of the product under customs classification 3206. In fact, average import price was far lower and landed price of imports was significantly below selling price of imports. Further, not only the price undercutting is positive, prices underselling is also quite relevant.

- g) The demand of the subject goods have not declined. The fact is that the imports reported by the DGCI&S and second resources are very much understated.

## 2.0 EXPORTERS:

### 2.1 M/s. Guangzi Dauha Chemical Factory, China (DAUHA)

- a) M/s. Dauha, a producer and exporter of subject goods, has fully cooperated with the Designated Authority ever since initiation of anti dumping investigations.
- b) In the preliminary finding recommendations, the Authority has declined to accept Dauha's claim for market economy status. They have requested the Authority for granting market economy statistics and the determination of normal value be based on domestic prices and costs in the final finding recommendations by the Authority and has submitted information on
  - i. Market conditions prevailing in M/s. Dauha.
  - ii. Legal criteria for market economy status
  - iii. Extracts of foreign trade law of Peoples Republic of China.
  - iv. Extracts of Regulation of Peoples Republic of China on imports and exports of goods.
- c) They have reiterated that M/s. Dauha, a producer and exporter of Titanium Dioxide is engaging in commercial transaction both in China and abroad based on market economy conditions.

### 2.2 M/s. Guangzi Cang Wu Titanium Manufacturing Co.Ltd. (GCWT)

They have stated that the M/s Cang Wu Titanium Dioxide manufacturing Company Limited which was controlled by the State Government before the year 1997 was changed the name to M/s Cang Wu Shun Feng Titanium Dioxide Co. Ltd, China, with effect from 28.7.2003. The reason for the change in the name is attributed to change over to private sector.

## IMPORTERS/USERS

### 2.3 M/s. Titanium Dioxide Agents, Dealers and Consumers Association of India:

The Association has welcomed the imposition of provisional anti dumping duty on Titanium Dioxide. They have stated that Chinese

goods are not only cheap but are of also poor quality standards. They have also requested that the authorities should keep watch on imports of 'rutile' grade in the under the grab of 'anatase' grade.

2.4 **EASTCORP International, Kolkatta**

The PHD Chamber of Commerce and Industry, Delhi, has forwarded a representation made by M/s Eastcorp International, Kolkatta vide their letter dated 8.9.2003. The importers have stated that the name of the producer in Sl.no 3 column 7 of the recommendation has been misquoted in the preliminary finding. The producer name should be read as 'Shaoguan Chemical Plant' instead of 'Shaoguan Chemical Plant Co. Ltd'. To this effect, they have enclosed a copy of a certificate from China Council for the Promotion of International Trade China Chamber of International Commerce.

C. **VIEWS OF INTERESTED PARTIES ON DISCLOSURE STATEMENT ISSUED BY THE DESIGNATED AUTHORITY:**

3.1. **VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:**

a. **On Product Under Consideration:**

The actual volume of imports reported in the disclosure statement are far higher than what has been reported by the petitioner under Chapter 28. Apparently, actual volume of imports under Chapter 32 is significantly higher than what has been assessed by the petitioner. This is due to the fact that the information provided by the petitioner was based on IBIS (which covered only few customs ports), whereas the information available with the Designated Authority, being from the DGCI&S, the same shows much higher import volumes.

Significantly higher volume of imports have been made under Chapter 32. Such being the case, petitioner requests extension of anti dumping duty on all titanium dioxide anatase grade, regardless of whether the goods are imported under Chapter 32 or 28. This is vital, as, in fact, substantial volumes are being imported under Chapter 32. Petitioner are afraid, should anti dumping duty not be extended to Chapter 32, imports may be allowed to be cleared under this sub-heading without payment of anti dumping duty.

Petitioner understands that between preliminary findings and by now, significant volumes of imports of the product under consideration have taken place under Chapter 32, without payment of anti dumping duty. They have submitted that, authority may clarify that all these imports shall be subjected to anti dumping duty; and anti dumping duty applies on the product under consideration regardless of classification under which it is reported.

b. On Dumping:

- a) The petitioner has stated that the claims of the exporter are such that it can be inferred that the exporter is trying to establish that (a) Chinese companies are market economy companies; and (b) Chinese State Owned/Controlled Companies are market economy companies. Further, petitioner has reiterated that, EC continue to deny MET to Chinese State Owned Companies. In fact, EC does not even grant individual treatment to such State Owned Companies.
- b) The following judgements of the EC have been referred by the petitioners in this regard:-
  - I. In the matter of Silicon originating in Russia, the EC has granted market economy treatment to the exporter on the basis of findings that the prices for the main raw materials for the Russian exporters were in line with world market prices as well as with the purchase prices of the community industry.
  - II. In the matter of solutions of Urea and Ammonium nitrate from Algeria, Belarus, Lithuania, Russia and Ukraine (where natural gas is the major product), the EC has not granted market economy treatment to the exporters based on the findings that state had an influence in the setting of gas prices.
  - III. In the matter of Certain Iron or steel Ropes and cables from Russia, the EC did not grant market economy status on the basis that for several important inputs the cost did not substantially reflect market values and financial statements audited in line with Russian standards which differed from the International Accepted Accounting standards.
- c) As regard to maintenance and auditing of accounts and procurement of assets, it has been submitted by the petitioner that when the company is a state owned enterprise, how can even be claimed that the capital of the company did not come from State.
- d) The Tax returns are filed by every enterprise – be a market economy company or non market economy. The filing of tax returns does not establishes market economy status or otherwise.

- e) Dahua's reference to a number of areas where price control exists even in India is misplaced. A company operating under Govt. control in "market economy country" and a company operating under Govt. control in "non market economy country" can not be put in the same footing, as has been attempted by the exporter in this case.
- f) The petitioners have submitted that the company is not entitled for MET. None of the other companies who have cooperated from China are also not entitled for MET, as has been rightly held by the Designated Authority.

c. **Dumping margin is on lower side:-**

Petitioners have submitted that the dumping margin assessed in the disclosure statement is on lower side given the best estimates of cost of production.

d. **On Injury And Causal Link:**

**Import volumes and market share:**

Actual volume of imports assessed by the Designated Authority are significantly higher than the known volume of imports for which the petitioner could provide evidence. Petitioner had been, in fact, all along the investigations arguing that the actual volume of imports is significantly higher than the volume of imports for which the petitioner could authentically collect evidence. Petitioner's difficulties in providing evidence of actual volume of imports is due to the fact that the information on this account is in possession of DGCI&S, which has been refusing to provide transaction wise data to the trade and industry.

**Factor affecting domestic prices**

It appears that the Designated Authority has disallowed service charges paid by the petitioner. Should such be the case, petitioner submits that the selling price of the domestic industry was also required to be adjusted appropriately, as the selling price of the domestic industry includes remuneration on account of service charges paid. Petitioner reiterates that comparison of non injurious price excluding service charges with net sales realization information provided by the petitioner would result in unfair comparison. It should also be noted that the cost of production information provided by the domestic industry is inclusive of service charges payable and, therefore, selling price information contained in costing information is also inclusive of service charges.

**e. On Non Injurious Price**

- a) While the factual element used by the Designated Authority in determining non injurious price have not been disclosed to the domestic industry. It is submitted that the NIP determined is far lower than the expected level based on the actual cost and fair return on capital employed. Accordingly petitioner has requested that the non injurious price assessed may kindly be reviewed again. Petitioner has submitted that the level of non injurious price determined would not be able to provide reasonable relief to the domestic industry.

**f. Duty on Fixed Amount Basis:**

The Designated Authority has recommended anti-dumping duty in terms of fixed amount. It is submitted that the final duties may please be recommended in terms of fixed amount only.

**VIEWS OF EXPORTERS:**

**3.2 M/s Guangxi Dahua Chemical Factory, China,**

**On Market Economy Treatment shall be given to Dahua :**

1. The exporters have stated that they have no comments to offer on General Disclosure.

2. The Authority has proposed not to grant market economy treatment to M/s Guangxi Dahua on the ground that the absence of significant state interference cannot be ensured as it is a state owned enterprise. In this regard, they have stated that, there are three levels of Government in China – Central, Provincial and City. Dahua is owned by a 'City' government which has no role or control whatsoever, in formulating industrial and economic policies. The role of a City Government shall not be confused with the role of a 'Provincial' or 'Central' Government. A city government is a local civic body with little jurisdiction over industrial and economic policies affecting the market conditions in which an industry operates. A city government basically looks after civic amenities and not industrial/economic policies. Such policies are decided by the 'provincial' or 'central' government as the case may be. Baise City Government is only an investor or entrepreneur in so far as Dahua is concerned. Therefore, market economy treatment cannot be denied to Dahua.

3. Dahua has provided ample evidence supported with documentary proof that decisions regarding price, costs and inputs including raw-materials, cost of technology and labour, output, sales

and investments are made in response to market signals reflecting supply and demand and that there is no state interference in this regard. These facts have been verified also.

4. Even assuming without admitting that there was some interference, it must be noted that the rules themselves permit 'some degree' of interference but they do not permit 'significant interference' by the state. In the instant case, there is no interference at all by the State as has been demonstrated by facts.

5. Under these circumstances, the decision of the Authority not to treat Dahua as an enterprise operating on market economy principles is bad in law. Dahua once again requests the Authority to reconsider this decision and grant market economy treatment to them.

6. The Authority has determined constructed normal value [CNV] based on cost of production of the most efficient producer in India after making appropriate adjustments with regard to raw materials, utilities and capacity utilisation plus a reasonable profit of 5% on cost of sales. M/s Guangxi Dahua submits that the above methodology is not one of the three methodologies prescribed under the Indian Anti-dumping Rules. Normal value shall be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-1 to the Anti-dumping Rules. In view of this, Dahua requests the authority to determine normal value based on the data submitted by them.

#### On Injury determination and examination of cause of link :

1. The import statistics given at paragraph 9.1 of the preliminary finding and the import statistics given at paragraph 1 of the disclosure statement differ in so far as they relate to the period of investigation. The imports from China were shown as 2040 MT in the preliminary findings which stand revised to 6362 MT in the disclosure statement. Similarly, imports from other countries were reported as 2505 MT in the preliminary findings which stand revised downwards to 2192 MT in the disclosure statement. From the foot-note given in the disclosure statement, it appears that the revision is due to the addition of transaction-wise detail of IBIS Mumbai and DGCIS reported under chapter 32.

2. Dahua objects to this revision on three grounds stated below:

a. It appears that the domestic industry has given additional data subsequent to the public hearing. This additional data was not part of their written submissions made pursuant to the public hearing. As an interested party we have not been made aware of the revisions to the import statistics submitted by the petitioner. We have not been given an opportunity to examine the revised data and offer our comments thereon.

b. Prima-facie, the revision appears to be unwarranted as there is a specific heading under chapter 2823.00. The heading reads as: 2823.00 Titanium Oxides.

c. Heading 3206 covers only pigments and preparations based on titanium dioxide. It does not, repeat, it does not cover titanium dioxide per se. The product under investigation is titanium dioxide and not pigments based on titanium dioxide. Just because the petitioner has claimed that titanium dioxide has been cleared in the name of 'Mica Pigments', that too based on the description given in the import statistics, the authority cannot include imports of pigments based on titanium dioxide to determine the volume of imports of titanium dioxide. Further, it amounts to an allegation of mis-declaration before customs. There is no warrant to entertain such allegations in an AD Investigation. Therefore, the revision is unwarranted.

d. Authority has stated that transaction-wise details as per IBIS Mumbai under Chapter 32 as well as imports shown under DGCIS under Chapter 32 have been added. This appears to be a case of double counting. It is not known whether the same transactions reported under chapter 32 by IBIS Mumbai have been reported under chapter 32 for DGCIS statistics also. It is also quite possible that the transactions reported under chapter 28 by DGCIS might have been reported under chapter 32 by IBIS Mumbai and vice versa. Therefore, it is not correct to combine the data from two different sources to arrive at total volume of imports. The Authority should either go by DGCIS data or by IBIS Mumbai data and not a combination of both.

e. Thus, the factual basis used by the Authority for determining the volume of imports into India is incorrect and the findings will be vitiated to that extent. Dahua requests the authority to redetermine the volume of imports and re-evaluate injury, etc. A revised disclosure statement may be made available to us for our comments.

f. The capacity utilisation has undergone such wide variation between the preliminary findings and the disclosure statement.

#### **Price under selling and Price under cutting are equal :**

a. The authority has observed that price under cutting was in the range of 10-20%. Further, the Authority has observed that the price under selling was also in the range of 10-20%. When price under selling and price under cutting are in the same range, NIP and sales realisation of the domestic industry shall be either same or pretty close. Under such circumstances, injury to the domestic industry cannot be established. Therefore, injury determination and causal link shall be held to be absent.

**On Incidence of Sales tax has not been considered in the causal link analysis :**

a. The sale from TTPL to KSIPTC involving levy of local sales tax at 30% and the second sale was from KSIPTC to the ultimate customer involving levy of CST at 4%. When the Kerala Government relaxed this condition and allowed TTPL to sell the product directly, within a very short span, customers have started buying from TTPL and TTPL has cleared all its stocks. Thus the injury was caused only by this peculiar method of sale followed by TTPL and not because of dumped imports. This fact has not been examined at all.

**M/s Indian Paint Association:** They have made similar submissions with regard to price underselling, price undercutting, incidence of sales tax and causal link analysis.

**3.3 M/s Cang Wu ShunFeng Titanium Dioxide Co. Ltd, China :**

M/s Cang Wu has made submissions by e-mail that "M/s Cang Wu ShunFeng Titanium Dioxide Co. Ltd, China" exports through "M/s ZheJiang Provincial Light & Textile Group Light Industry Co. Ltd." and a certificate has been furnished during the verification

Dumping margin based on domestic prices would workout to around 10% against 26.9% determined by the authority.

**VIEWS OF IMPORTERS:**

**3.4 M/s.CHEMI ENTERPRISE.**

The importer/user has vide submissions dated 14.7.2003 has observed that: The injury analysis is related to only TTPL and its selling price during the period of investigations viz. 1.1.2002 to 31.12.2002, was subject to double taxation.

- a) Decline in quantity of sales of the domestic industry may be attributable to the fact that during the period of investigation and even earlier considerable quantities of the subject material might have been imported from China and cleared duty free under various export promotion schemes and found their way into the domestic market.
- b) Subsidised and non-subsidised imports of the subject material from the subject country is not shown and considered and similarly demand and supply data of local producers is also not given and considered whereas it is claimed by the petitioners that they produce 57% of domestic production and therefore, it is necessary to verify the actual production consistency thereof and how the balance is met and the demand is also met.

- c) Levy of anti dumping duty is actually eliminating the competition and also eliminating the choice available to the domestic consumer.
- d) Normal value and ex-factory price and dumping margin are not given and therefore, it gives way to believe that dumping duty is levied on assumptions and also unilaterally.

M/s Chemi Enterprise, vide submission dated 25.8.2003 has stated that:

- a) Titanium Dioxide Anatase Grade is a general name and therefore the goods compared are not similar because they are not commercially interchangeable having regards to quality reputation existence of trade mark and country of origin and applicability whereas the goods produced by the petitioners are standardized as per ISI-(BIS) and has a brand name AJANTOX'A is 111:1991 and therefore not comparable with the imported Chinese material.
- b) Titanium Dioxide anatase grade manufactured in China is not equal to the standard of the material produced domestically. The domestic material fetches higher price than the Chinese material on account of its quality and acceptability.
- c) In view of the quality difference the domestic produced material always fetches higher price than the Chinese material and the difference in selling price is not much so as to cause injury to the domestic industry.
- d) Titanium Dioxide anatase is imported from different countries and the price is not the same because the price varies from one brand to another depending upon its quality reputation, acceptability and applicability etc.
- e) After initiation of investigation the petitioner has done away with the marketing intermediary (KSIPTC) and done away with the double taxation and allowed discounts to their stockists and registered a comfortable rise in sales and thereafter immediately on imposition of provisional anti-dumping duty increased the prices and in this way the benefits went to the stockists rather than the petitioner or the labour.
- f) The demand projected shows a future gap of 8,400M/T and therefore there is a gap between demand and supply of anatase grade titanium dioxide and therefore, the question of injury or threat of injuy to the petitioner is out of question and there is no possibility at all of its being shut down at any time in future on account of such meagre duty paid imports from China which are negligible. The estimated demand level for anatase grade titanium dioxide for the period 2001-2002 is 22,500 M/T.

- g) Consolidated imports of titanium dioxide anatase grade where maximum 2,200 M/T during 2001-2002 and minimum 1,500 M/T during April 2002 to July, 2002.
- h) Indian manufacturers and production level of anatase grade Titanium Dioxide for the period April 2001 to March 2002.
- i) The investigation initiated by the Authority needs be terminated for the reason stated above and withdraw the anti dumping duty provisionally imposed must be withdrawn in the interest of justice and fair play.

**D EXAMINATION BY THE AUTHORITY:**

- 4.0. The submission made by the exporters, importers, domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter. However, certain crucial issues raised by different interested parties have been examined as under:-
- a. With regard to the issue raised by the petitioner in respect of non injurious price determination and assessment of net sales realisation it is clarified that the authority called the representative of the petitioners and the methodology adopted was explained. It was further explained that the comparison of the non injurious price with net sales realisation and the landed value has been made at appropriate comparable levels.

**On issue of product under consideration**

The product under consideration Titanium Dioxide Anatase type is classified under Chapter 28 under Sub-heading 28 23 00 01. After the preliminary findings it has come to the light that substantial volumes of imports have been made under Chapter 32 also . For the purpose of Disclosure Statement Authority considered imports under Chapter 28 for the period of investigation and under Chapter 32 IBIS data for the period January to March, 2002 and DGCI&S data for the period April to December, 2002. Authority has called for transactionwise details of imports from DGCI&S, Kolkata for Chapter 28 and 32 which has been received. Subsequently, higher volumes of imports of subject goods have been reported under Chapter 32. In the circumstances, the Authority has picked up imports volume reported under Chapter 28 & 32 with respect to Titanium Dioxide, Anatase type for the purpose of this investigation and ensured that double counting of imports is avoided in its analysis.

**On issue of Like Article by M/S. Chemi Enterprise:**

The importer/user has raised that the domestic material is of higher quality with a brand name Ajantox-A, vis-à-vis, Chinese material is of lower quality and available at lower price. The Authority notes that this is only an argument without substantiation. Further, it notes that none of the cooperative producers/exporters have raised the issue of brand or the quality in this investigation. Hence, argument raised by importer/user is rejected.

As regards the argument raised about duty free imports of subject goods from subject countries during the period of investigation under advanced license/several export promotion schemes, Authority notes that the subject goods which are destined for domestic market under DTA attracts all duties including anti dumping duties.

Evidence given in form of PIE chart indicating imports volumes for different countries including Germany is for the period April 1998-March, 1999 and is not for the period of investigation. Hence the Authority rejects the evidence.

Authority notes that the extracts of market price as reported by Industrial Chemical and Solvent (Chennai) dated December, 7,2002 does not indicate/clarify whether the subject goods is imported under duty free schemes.

As regards to sale of subject goods by the petitioner companies during the period of investigation was subject go double taxation and their selling price was in competitive. Authority notes that M/s. TTPL was selling its products through same outfit even before the period of investigation and during the investigation period.

**On claims of Market Economy status for M/s Dauha:**

Reference is drawn to the analysis made by the Authority in para 8.1 of the Preliminary Findings dated 6<sup>th</sup> June 2003. In this regard Authority notes that M/s.Dauha has furnished additional information in form of evidence while claiming market economy status; however, the Authority is unable to apply the principles set out in paragraph 1-6 of Annexure I of the Rules Supra and is constraint to proceed as per para 7 of annexure I whereby normal value can be determined on any other reasonable basis including price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to including a reasonable profit margin. Authority confirms this findings on non-market economy status for M/s. Dauha as per preliminary findings. For the purpose of final finding the information furnished by the exporter on whom market sales, cost of production and claims of market economy status has been examined. Authority notes that the company has admitted in its submission that

Dauha is a State-owned enterprise governed by the law of Public Republic of China on Industrial Enterprises and the regulation for transformation of operational mechanism of state owned industrial enterprises. The Baise city government, Guangxi province is the sole share holder of the enterprise. Accordingly, Authority concludes that the absence of significant state interference in this case can not be ensured and thus does not satisfy the criteria under the rules. For this reason, the Authority has not granted market economy treatment to this company.

#### **E PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

- 5.0 a) The product under consideration in the present investigation is Titanium Dioxide Anatase grade, having chemical formula  $TiO_2$ .

Titanium Dioxide can be in Anatase form or Rutile form. However, the present investigation is against Titanium Dioxide in Anatase form only.

Titanium Dioxide Anatase is produced from ilmenite, which is a mixture of titanium, ferrous iron and ferric iron. Titanium in ilmenite is extracted by reacting this raw material with sulphuric acid. Titanium goes into the solution as titanium oxy sulphate. Titanium dioxide is obtained from titanium oxy sulphate by injecting live steam and dewatering the treated pulp.

Titanium Dioxide ( $TiO_2$ ) occurs commonly in oxide form. Properties of the subject goods are described in terms of refractory index, specific gravity, hardness, crystal structure, oil absorption, colour, hiding power, ultra violet light absorption, resistance to chalking, etc.

- b) Titanium Dioxide is an inorganic chemical. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. Complete description of the product under Customs Tariff and under ITC is as under: -

Chapter/ Sub-heading	Description
28	Inorganic Chemicals
2823	Titanium Oxide
282300	Titanium Oxide
28230001	Titanium Dioxide, Anatase type

Even though the product has dedicated classification, it has been found from the DGCI&S transaction wise import data that the product is being reported in very substantial quantities under customs classification 3206. Authority found that the exports reported by two responding

exporters itself are in the region of imports reported by the DGCI&S under classification 2823.

Titanium Dioxide is a pigment and is primarily used in the manufacturing of paints, plastics, paper, ink, rubber etc. Titanium Dioxide Anatase is used in the production of the following:-

- All type of white and pastel shades of paints,
- White walled tyres and car tyres,
- Printed fabrics,
- Electronic components,
- Foot wear and leather goods,
- Flooring materials like linoleum, white mosaics;
- De-lustering of artificial fibre in Textile Industry.

Titanium Dioxide (Anatase) has a very high degree of whiteness. Its tinting strength and hiding power are superior to any other white pigment and it also has stability & durability against light and heat. It is not toxic. Imports of the product are allowed under Open General License (OGL) Policy.

As regards Chemi Enterprise's argument on product and like article, the Authority notes that decline in the sales volumes and market share of the petitioner in particular and Indian Producers in general and increase in import volumes and market share of the imports from China on the other hand does not suggest a possible difference in the product. In fact, it has been argued by some other party that the sales of the Indian Producers have once again increased after imposition of ADD. It is also relevant to point out that the arguments on alleged quality difference are unsubstantiated and unquantified with verifiable evidence.

## F LIKE ARTICLE

6.0 Petitioner has claimed that the subject goods produced by the petitioner are like article to the subject goods imported from China. Petitioner claimed that there is no known difference in Titanium Dioxide exported from China and Titanium Dioxide produced by the petitioner company.

In order to examine whether Titanium Dioxide produced by the domestic industry and imported from China are comparable, characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods were relied upon. It is found that the subject goods imported from China and goods produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable. The consumers are using

the two interchangeably. There is no argument disputing the claim of the petitioner on this account.

In view of the above, the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the goods imported from the subject countries, within the meaning of the Rules.

#### **G DOMESTIC INDUSTRY**

- 7.0 There are three producers of Titanium Dioxide Anatase Grade in the country. Other producer of Titanium Dioxide, namely Kerala Minerals & Metals Limited. However, the company produces only Rutile Grade. All the producers are members of the Association. Petition was filed by the Association comprising all the producers of the subject goods. M/s. Travancore Titanium Products Limited, Travancore is the petitioner company who has provided all relevant information in the petition. Other two producers, namely M/s. Kolmak Chemicals Limited and Kilburn Chemicals Limited have specifically supported the petition.

Subsequent to initiation, M/s. Kolmac Chemicals have also provided costing information along with relevant injury information. Production of Travancore Titanium Products alone accounts for more than 50% of Indian Production.

The petitioner, therefore, satisfied the criteria laid down under Rule 5(1), 5(3) and explanation to Rule 5(3). Further, Travancore Titanium Products and Kolmac Chemicals have been treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules.

#### **H. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:**

- 8.0 Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -
- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third

- country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export or there is no comparable price in the country of origin, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The Authority also notes the various Customs Notifications NO.44/99(N.T) dated 15<sup>th</sup> July, 1999, No.28/2001(N.T) dated 31<sup>st</sup> May, 2001 and No.1.2001(N.T) dated 4<sup>th</sup> January, 2002 on the Anti Dumping Rules.

The Authority provided opportunity to the exporters from subject countries to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority wrote to the Embassies of subject country in India also. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of export price and normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act. Responses were received from the following exporters from China PR:-

- a) M/s Guangxi Dahua Chemical Factory, China( Dahua)
- b) M/s Guang Xi Xing Mei Xiang Titanium Dioxide Co Ltd, China;
- c) M/s Guang Cang Wu Titanium Manufacturing Co Ltd, China;
- d) M/s Shaugan Chemical plant , China;

Details of normal value and ex-factory export price determination is given below.

#### **M/s Guangxi Dahua Chemical Factory, China( Dahua) :**

The exporter has furnished information in the Exporters Questionnaire. The transaction wise information relating to Sales in home market, exports to India, sales price structure for exports to India and Domestic market , Factory cost and profit in App 1-8 respectively have been furnished.

M/s Dahua in their submissions has claimed that the company is operating on a market economy principles. They have submitted that Guanzxi Dahua Chemical Factory satisfies each of the four conditions laid down under paragraph 8(3) of the Anti dumping Rule s and thus is entitled to be treated as

a market economy company in terms of the proviso to paragraph 8(3) and under the circumstances, the Authority shall apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 of Annexure 1 for the purposes of determining normal value, export price and margin of dumping in so far this company is concerned.

In the preliminary finding, the Authority had noted that it was unable to apply the principles set out in paragraph 1 to 6 of Annexure 1 of Rules supra and is constrained to proceed as per para 7 of Annexure-1 whereby normal value can be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin.

Vide their submissions dated 1.9.2003, M/s GUANGXI DAHUA CHEMICAL FATORY, CHINA , submitting reclaim for Market Economic Status.

The company disagrees with the preliminary findings in this regard. Again Dahua claims that market economy status be granted and normal value be based on its own prices and costs by the Designated Authority in the final proceedings. This submission addresses particularly the issue of normal value in the context of paragraph 8.1 of the Preliminary Findings Notification.

#### Market Conditions Prevailing in Dahua

It is claimed that it has full control on inputs/outputs, pricing, exports, domestic sales, operations, personnel, investments and other operating issues along with sufficient evidence. Accordingly, Dahua meets those criteria as described in paragraph 8.1.3 of the Preliminary Findings Notification, sub-para (3) of the Rules.

It is also claimed that Dahua chooses sources of best competitiveness. Based on the market situation as well as production need, Dahua selected different suppliers for materials needed by contract or in a spot market.. A complete list of all suppliers for each item along with their prices, ownerships and addresses is furnished. However, these suppliers, no matter private or state-owned, are all operating under market conditions. To Dahua, the only consideration is price and quality of raw materials they have offered. Dahua did not select any foreign supplier during the period of investigation.

- (i) Dahua purchased coal gas from a private company, coal from 6 companies, 4 of which are privately owned. Besides, Dahua did not purchase water from any party but producing by itself. Relevant information of utilities suppliers for Dahua's production during the POI is furnished. Dahua is

charged at normal rates for usage of utilities. To the best knowledge of Dahua, these suppliers of utilities were not subsidized.

(ii) Considering costs and quality, Dahua purchased all needed raw materials in domestic market, rather than importing from foreign market. In that sense, no restrictions or conditions on imports of raw materials applied to Dahua.

(iii) As a general practice, Dahua employs workers by contracts. Contractual workers are generally organized in the light of the specific production flow to work for no more than 40 hours a week. Prior to their posts, workers must be strictly trained. For some special titles as electricians and welders, relevant certificates/qualifications are required.

(iv) Dahua has full autonomy to decision-making on pricing and output quantity. No local/regional authority or State is involved in Dahua's process of product manufacture and sale, by law or in practice.

(v) The Balance Sheet and Income Statement of Dahua audited by Guangxi Guixincheng Accounting Firm must be filed annually with the local taxation administration and financial administration.

a) Dahua applies to the *General Principles of Financial System for Enterprises, Financial System for Industrial Enterprises, Accounting Standards for Enterprises and Accounting System for Industrial Enterprises* enacted by the Ministry of Finance of the People's Republic of China in 1992. sets concerned.

b) Dahua obtained its fixed or intangible assets on the open market, rather than receiving from any government agencies or other enterprises freely or with discount. For instance, Dahua bought machinery, mechanical apparatus and other production equipment on the open market; and gained buildings by contractual construction between Dahua and construction companies. Dahua's Record of Fixed/intangible Assets as dated of December 31, 2002 is furnished.

(vi) Dahua did not lease or rent any facilities used for production and/or commercial purposes.

(vii) As of the date of 31<sup>st</sup> December, 2002 Dahua held loans taking from the Bank of China Beise Branch and the Industrial and Commercial Bank of China Beise Branch. Both banks providing loans to Dahua are commercial banks and operating under market economy conditions. Dahua did not receive any special loan or subsidized schemes. A list of loans held by Dahua by the end of 2002 is furnished.

(viii) Under the *Regulation of Foreign Exchange Administration*, exchange rates between the RMB and foreign currencies are based on supply-demand mechanism on the market, and there is a single, managed floating rate. The people's Bank of China, the central bank, publishes the daily exchange rates in line with the price on the inter-bank exchange market.

Following this system, Dahua may buy foreign currencies from banks with RBM for purchase of inputs, at the rate of the transaction date. Similarly Dahua sells its earnings in foreign currencies to banks at the rate of the transaction date. However, Dahua is a new player in international market and has not applied for a foreign currency account so far.

(ix) Dahua did not conduct barter-trade or counter-trade in the last five years.

(x) Dahua did not conduct barter-trade or counter-trade in the last five years either.

## 2. Legal Criteria for Market Economy Status

In its first claim, Dahua quoted both Indian Anti-Dumping Rules and the WTO Protocol on China's Accession justifying that Dahua meets those criteria for market economy status. Dahua believes that its manufacture, production and sales of the subject product are based on commercial considerations and entirely reflect the market signal.

The Designated Authority also pointed out in the Preliminary Findings Notification that, some text/phrases like "mandatory plan" or "policy losses" in relevant laws and regulations indicates that Dahua is not operating under

market economy conditions as envisaged under paragraph 8 of Annexure I Rule Supra. Dahua could not agree with that. As a matter of fact, mandatory plan has been erased long before in most commercial fields in China, and price control on products has been cut down dramatically. Also as a member of the WTO, China is obliged not to launch any price control upon products or services unless otherwise listed in Annex 4 of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China and to reduce them in the future, as explicitly stated in paragraph 56 of the Report of the Working Party on the Accession of China. Both raw materials Dahua used for production of the subject product and the subject product itself fall out of the list of government price control by Chinese authority.

In terms of export activities, China cut down much control on export activities and generally allowed for free import and export of goods as early as 1990's. According to Article 15 of the Foreign Trade Law of the People's Republic of China ("Foreign Trade Law"), "the State allows free import and export of goods and technologies". Moreover, a new regulation concerning export of commodity was issued one day prior to China's accession to the WTO, permitting free, fair and orderly international trade. Article 4 of the Regulations of the People's Republic of China on the Import and Export of Goods ("Regulations on Goods Import and Export") provides that "The State shall permit the free import and export of goods, and shall ensure, in accordance with the law, that import/export trade is fair and orderly. Apart from goods that are categorically prohibited or restricted under the law or administrative regulations from being imported or exported, no organization or individual shall put in place or maintain measures that prohibit or restrict the import or export of goods." In this context M/s Dahua has cited Annex 4 of the Protocol.

The product concerned and the raw materials used for the manufacture of the product concerned are not subject to price controls in China.

(a) Price controls on select products like natural gas and pharmaceuticals still exist. Pharmaceuticals are subject to price controls in many countries including India especially life saving drugs, bulk formulations of generic drugs, etc. Similarly, India had kept Natural Gas under the Administered Price Mechanism till recently.

(b) In China, agricultural products like Durum wheat, etc are subject to government guidance pricing. This is akin to the Minimum Support Price and the Minimum Price for Import of such goods prevailing in India in the agricultural sector. Urea is subject to Government guidance pricing in China. In India, Urea is still under administered pricing with substantial subsidy from the Government's treasury.

(c) Even in India, public utilities like gas, water, electricity, etc were subject to government pricing till recently except in some areas, due to entry of private players, government pricing has ceased to exist in respect of services rendered by government departments, local authorities or government corporations such as Irrigation Department, State Electricity Boards, State/UT water boards, municipal corporations, river valley authorities, etc. Such price controls do not make India a non-market economy. Similarly, price controls in these public utilities shall not be taken to mean that China continues to be a non-market economy.

(d) In the services sector, government pricing is prevailing in China in respect of postal and telecommunications services, entry fee for tour sites, education services, etc. Needless to say that in India also, these services are subject to Government pricing even today.

(e) Rail Freight and Railway passenger fares are subject to Government guidance pricing in China. In the case of India, they are controlled by the Government itself. The railway fares are approved by Parliament as a part of Railway Budget. This does not mean that India is a non-market economy country.

Thus, China has dismantled its price controls on almost all items except a few goods and services on which many of the market economy countries and western developed economies continue to have price controls. Therefore, China shall be treated as a Market Economy.

In paragraph 8.1.6 of the Preliminary Findings Notification, the Designated Authority also addressed the Business License and minutes of session furnished by Dahua. Dahua wants to restate that "state ownership" means nothing of government interference in Dahua's business operation. As proofed by sufficient evidences, Dahua, as one of the market players in both domestic and international market, is acting independently and is responsible for its own profits and losses. Dahua furnished the copy of minutes of session in year 1997 rather than during the POI in its first claim for the reason that it was the session when the present general manager Mr. Su Yaowei was elected and appointed then. In Annex 2 to the first claim it was described that a new factory director of Dahua was elected. However, there is no difference between the post of general manager as mentioned in the first claim and factory director as called in its Annex, both of them indicating the head of Dahua, Mr. Su Yaowei. Dahua will be willing to provide further information in this regard, including minutes of session in the POI as well as evidence of the post concerned.

The exporter has cooperated with the investigation and the exporters' information was verified for determination of normal value and export price.

### **Examination by the Authority :**

The authority has examined the submissions made by the interested parties with regard to the treatment of the co-operating exporter as Non-Market/Market economy entities in China PR. Relevant Rules governing such treatment are as under:

#### **"15. Price Comparability In Determining Subsidies and Dumping"**

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
  - (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
  - (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

**Position Under Indian Law at time of initiating matter:**

8. The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in that note and includes any country which the Designated Authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the designated authority shall consider as to whether, -

- (i) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this

*paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.*

*Note :- For the purposes of this paragraph, the list of non market economy countries is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakhstan, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the designated authority.]*

### **Position Under Indian Law Post 4th January 2001:**

**Rule 8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)**

**(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country.**

*Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*

**(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether :**

**(a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;**

**(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy**

system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

*Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".*

Vide Notification No. 1/2002NT Customs dated 4.1.2002. Para 8(1)(2) & (3) was amended.

Vide Notification 101/2003 dated 10<sup>th</sup> Nov., 2003, the para (4) was inserted after Sub-paragraph 3(d) in Para 8 of Annexure 1 to Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.

"(4) Notwithstanding anything stated in sub-paragraph (2) above, the designated authority may treat a country as market economy country, if, based on a detailed evaluation of the relevant criteria as contained in a public document, the said country has been determined to be or has been treated as a market economy country recently by a WTO Member for the purpose of anti-dumping investigation. Criteria which may be relevant in this respect include those specified in sub-paragraph (3) above."

The Authority notes that the WTO gives the option of treatment of China for the purposes of application of Anti Dumping or subsidy measures to the Member state.

1. A perusal of the entire clause above show that there is nothing to preclude a WTO Member from granting full market economy treatment to China or partial market economy treatment to companies or exporters from China. In fact, a Member is also empowered to grant market economy status to China as a whole.
2. The Indian law clearly provides that the companies operating in China can be treated as Market Economy if they satisfy the conditions laid down under the Rules.

3. With the onus shifted on the party claiming the market economy status, the Indian law, clearly prescribes the criteria prior to any company/entity getting market economy status from a Non-Market economy.
4. On each of the four criteria as per para 8 of Annexure I of Anti dumping Rules, the exporters provided detailed submissions, which were verified by the Authority.
5. In light of the above, giving market economy treatment and accepting the cost of production supplied by the cooperating exporter from China, who has fulfilled the criteria for market economy treatment in accordance with the laws of India is fully within the powers of the Designated Authority and compatible with India's commitment to the WTO.

The Authority has examined the status of cooperative exporter from China PR in light of the above.

#### **M/s Guangxi Dahua Chemical Factory, China( Dahua) :**

The information furnished by the exporter on home market sales, cost of production and the claims of market economy status has been examined. Authority notes that the company has admitted in its submission that M/s Dauha is a state owned enterprise, governed by the Law of People Republic of China on Industrial Enterprises and the Regulation for transformation of operational mechanism of State owned Industrial Enterprises. The Baise City Government , Guangxi Province is the only share holder of the enterprise.

Accordingly, the Authority therefore concludes that the absence of significant state interference in this case cannot be ensured and thus does not satisfy the criteria under the Rules. For these reasons the authority has not granted market economy treatment to this company.

**M/s. Guangzi Cang Wu Titanium Manufacturing Co.Ltd. (GCWT)**

**M/sGuangxi Xing Mei Xiang Titanium Manufacturing Co. Ltd. (GXMX)**

**M/s. Zhejiang Provincial Light & Textile Industry Group Company, Hangzhou, China. (ZPLT)**

Both the exporters information along with the trading house ZPLT has been verified by DGAD. The exporters from GCWT have furnished supplementary information on normal value and export price for consideration. Though the company claimed for market economy status, no information substantiating the claim of market economy status has been furnished. Vide their fax from M/s ZPLT dated 6<sup>th</sup> February,2004 requested more time to submit the information on market economy. As the investigations are time bound, the Authority has decided to go ahead with the best available information on record.

M/s. GXML has failed to cooperate fully during the verification visit and furnish the information in the form and manner prescribed by the Authority. In the circumstances, Authority discarded the information for the purpose of final finding.

**M/s GCWT & M/s GXML :**

The company furnished information on home market sales in the prescribed questionnaire. The Chinese producer claimed to be fully independent from state interference and stressed that its private status be taken in to account . However, information on market economy status was neither furnished before nor during the verification visit. The information submitted on 16.2.2004, subsequent to the verification visit on their claim of market economy status was not verifiable and hence it is rejected.

**Normal Value**

**M/s Guangxi Dahua Chemical Factory, China( Dahua ) :**

The Authority notes that the company has admitted in its submissions that it is a state owned enterprise. For the purpose of the final finding, the information /evidence furnished by the company with regard to market economy does not meet the criteria laid down under the Rules. The Authority considered, out of a number of options provided under the Rule, the best option to be applied for assessment of normal value. The Authority notes that the following options are provided under the Rules:-

1. the price in a market economy third country,
2. constructed value in a market economy third country,
3. the price from such a third country to other countries, including India.
4. the price actually paid in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
5. the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin.

It is noted that constructed value in a market economy third country or price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin are most appropriate basis in the instant case. In fact, price in a market economy third country, such as India or price from third country to other countries, including India would have, at best, resulted in higher normal value. At the same time, it is possible that such prices are not reflective of true and representative prices. Under the circumstances, the authority has based the normal value on constructed cost of production by adopting information available on cost of production of the most efficient producer in India by making

appropriate adjustments with regard to raw materials, utilities and capacity utilisation. A reasonable profit of 5% on the cost of sales is considered for determination of the normal value. The Normal Value thus works out to \$\*\*\* per Mt of the subject goods.

#### **Export Price:**

The exporter has furnished transaction wise details for export sales to India during the period of investigation along with Sales price structure in App 4. Adjustments have been claimed on account of discounts/commission (\$\*\*\*), inland freight(\$\*\*\*), taxes(\$\*\*\*), overseas freight (\$\*\*\*) and insurance(\$\*\*\*) and the same after verification have been adopted. The authority after due verification of the information submitted by the exporter has adopted the Export Price as \$\*\*\* Mt at ex-factory level.

**M/s Cang Wu ShunFeng Titanium Dioxide Co. Ltd, China**  
 (formerly named M/s Guangxi Cang Wu Titanium Manufacturing co. Ltd, China.) (GCWT)

#### **Normal value**

The company furnished information on home market sales in the questionnaire response. It was noted during the verification that the company has effected domestic sales through M/s ZheJiang JiaXing Oil and Paints Factory, China and M/s GuangZhou HuangPu BaiHe Pigment Co, Ltd, China. Exports sales through M/s ZheJiang Provintial L & T Group Light Industry Co Ltd, Hang Zhou (ZPLT) and M/s GuangXi Chemical Import and Export Company. The status of M/s GuangXi Chemical Import and Export Company which is a trading company is not known as they did not cooperate with the investigation. Though the producer company viz. Cang Wu has furnished all details for domestic sales, transaction wise. It is noted that the information provided on domestic sales activity was incomplete and inadequate as the sales chain for domestic sales to independent consumer through Retail / Distributor/trader has not been furnished and no evidence to that effect was given during verification. Information on market economy status was neither furnished before nor during the verification visit. The information submitted on 16.2.2004, subsequent to the verification visit on their claim of market economy status was not verifiable and hence it is rejected. Under the circumstances, the authority has based the normal value on constructed cost of production by adopting information available on cost of production of the most efficient producer in India by making appropriate adjustments with regard to raw materials, utilities and capacity utilization. A reasonable profit of 5% on the cost of sales is considered for determination of the normal value. The Normal Value thus works out to \$ \*\*\* per Mt of the subject goods.

**Export Price:**

The exporter has furnished transaction wise details for export sales to India during the period of investigation along with Sales price structure in App 4. Since Exports sales through M/s ZheJiang Provintial L & T Group Light Industry Co Ltd, Hang Zhou (ZPLT) has been furnished, the Authority has considered adjustments on account of inland freight (\$\*\*\*), taxes (\$\*\*\*), overseas freight (\$\*\*\*) and insurance(\$\*\*\*) to arrive the ex factory Export Price. The authority after due verification of the information submitted by the exporter has adopted the Export Price as \$ \*\*\* per Mt. of subject goods at ex-factory level. As regards to volumes of sales made through M/s GuangXi Chemical Import and Export Company who did not cooperate with the investigation it would fall under residual category.

**Guangxi Xing Mei Xiang Titanium Manufacturing Co. Ltd. (GXML)**

During the verification visit the producer company did not furnish relevant information on cost of production, domestic sales, sales to other countries, adjustment, export price, audited accounts etc for verification. In the circumstances, Authority treats the company as non-cooperative and has not determined separate dumping margin for the exporter. The company would fall under the residual category.

**M/s Shaoguan Chemical Plant, China**

Authority noted in the preliminary finding that the exporter response to exporters questionnaire is grossly deficient and inadequate in many respect.:.

1. There is no response to the general descriptive part of the questionnaire (A to H of the questionnaire).
2. Appendix-7 has not been provided.
3. Month-wise sales in Appendix-3 does not appear to have been given for all the months of the investigation period.
4. Transaction wise sales in Appendix-1 does not appear to contain all sales in the domestic market.
5. Annual reports for the past two years and investigation period not provided.
6. There is no claim that the company can be treated as market economy company.

There has been no response after the preliminary findings and the exporter is treated as a non cooperative exporter and separate dumping margin has been determined for the exporter. The company would fall under the residual category

#### **M/s Maanshan Chemical ( Group) Co. Ltd, China**

The authorized representatives in India furnished the authorisation letter from the exporter and collected the non confidential version of the Petition for making submission to exporters questionnaire. However, no response has been filed. In the circumstances, Authority has treated the exporter as non-cooperative exporter for the purpose of this investigation (Rule6(8)).

#### **Jiaozuo General Chemical Plant , China**

The exporter has stated that their plant is a State owned Comprehensive Inorganic chemical plant with four branch companies. They have also stated that the subject goods are classified under HS code 32061110 in China Customs. They have not kept any business relationship with the importers listed in the petition. They have furnished some evidence from Custom Data Chart to support their claim. In the circumstances, Authority has treated the exporter as non-cooperative exporter for the purpose of this investigation (Rule6(8)).

#### **Panzhihua Iron & Steel Group Cropn. , China**

The authorised representative in India stated that the exporters wish to cooperate with the investigation. However, no response has been filed. In the circumstances, authority has treated the exporter as non-cooperative exporter for the purpose of this investigation.

#### **Guangxi Baihe Industry co. Ltd. , China**

The exporters requested for extension of time to file the questionnaire response, which was considered by the Authority and allowed time up to 17.3.2003. However, no response has been filed. In the circumstances, authority has treated the exporter as non-cooperative exporter for the purpose of this investigation.

#### **For Non Cooperative Exporters:**

The authority has based the normal value in respect of all non cooperative exporters on constructed cost of production by adopting information available on cost of production of the most efficient producer in India by making appropriate adjustments with regard to raw materials, utilities and capacity utilization. A reasonable profit of 5% on the cost of sales is considered for determination of the normal value.

The Normal Value thus works out to ( \$ \*\*\* ) per Mt of the subject goods. As regards to export price it has been based on the lowest export price transaction ( \$ \*\*\* ) of a cooperative exporter in the investigation being the best available information with the Authority in accordance with Rule 6(8).

## DUMPING MARGIN

The rules relating to comparison provides as follows:

*"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."*

The authority has carried out normal value comparison with the weighted average ex-factory export price in period of investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporter/ producers of the subject country wherever appropriate.

The dumping margin so assessed are significant and above de minimus limits prescribed under the Rules. The dumping margin for exporter/ producer of the subject goods from the subject country are as under:

S N	Exporter/ Producer	Normal Value (\$/MT)	Ex-factory Export Price (\$/MT)	Dumping Margin \$/MT	Dumping Margin as % of Export Price
1	M/s. Guangxi Dahua Chemical Factory ,China (Dahua)	***	***	***	23.9%
2	M/s M/s Cang Wu ShunFeng Titanium Dioxide Co. Ltd, China exports through M/s ZheJiang Provincial Light & Textile Industry, China (ZPLT), Haugzhou, China PR	***	***	***	26.9%
3	Other Exporters	***	***	***	27.9%

I. **INJURY AND CAUSAL LINK:**

9.0 The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

- i. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- ii. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 19 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, Authority may consider such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.

It has been pointed out by the domestic industry that the Authority seems to have adjusted the net sales realisation and cost of production of the domestic industry. Petitioner has pointed out this seems to have not been appropriately reflected in the disclosure statement in terms of certain parameters (cost of production, selling price, profit/loss, cash flow, return on investment). This has been appropriately taken care in these findings.

**9.1 Import volumes and market share :**

Particulars	1999-00	2000-2001	2001-2002	POI (Jan,02 - Dec,02 )
<b>Imports (MT)</b>				
China PR	359	1069	1543	6362*
Other Countries	2894	2177	2622	2192*
Total Imports	3253	3246	4165	8554
Sales of dom industry	17286	17011	14921	12265
Other producers	3739	3920	4972	5966
<b>Total Demand</b>	<b>24278</b>	<b>24177</b>	<b>24058</b>	<b>26785</b>
<b>Share of imports</b>				
Share of China PR	11%	33%	37%	74%
Share of others	89%	67%	63%	26%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Share in Demand</b>				
China PR	1%	4%	6%	24%
Other countries	12%	9%	11%	8%
Domestic industry	71%	70%	62%	46%
Other Producers	15%	16%	21%	22%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\* Figures include imports reported by DGCIS under Chapter 28 & transaction wise details by IBIS, Mumbai (for period Jan – March,02) and DGCIS (for period April – December,02) under Chapter 32.

The imports from various countries, their share in terms of imports and demand in India is given above. It has further been pointed out by the petitioner that the imports are being reported under other customs classifications also by DGCI&S. In support of the same they have provided information of the exports statistics claimed to be published by Chinese Government and transaction wise data from the Secondary Sources. The petitioner has also submitted details of imports statistics published by DGCI&S in respect of other products showing imports of the subject goods reflected in those details. The Authority also notes that the imports figures reported by the DGCI&S is about 30% lower than the imports details submitted by the cooperating exporters in this investigation. It has been submitted by the domestic industry that the imports of subject goods reported under chapter 28 by DGCI&S is incomplete. Further it was stated that the imports are reported under chapter heading 3206 (Mica Pigments) also. A transaction wise analysis of the imports reported under sub head 3206 (Mica Pigments) by DGCIS and IBIS , Mumbai was made. This analysis shows that the volumes of imports of the subject goods during period of investigation of Titanium Dioxide (anatase) to the tune of more than 6000 mt from

China PR and more than 2000 Mt in respect of other countries. Total exports of the subject goods by responding exporters works out to 3087 MT during the period of investigation. Thus, it is evident that a number of actual exporters have not cooperated with the Authority.

The Authority observes that: -

- a) Imports from China have increased in absolute terms;
- b) Imports have increased in relation to production of the domestic industry in India;
- c) Imports have increased in relation to demand of the subject goods in India. At the same time, share of the domestic industry has declined.

It is thus evident that there has been a significant increase in dumped imports, both in absolute terms as also relative to production and consumption in India. Imports show a clear adverse volume effect. The adverse effect is significant and material.

With regard to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, the Authority considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports was otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases to a significant degree which otherwise would have occurred. For the purpose, the Authority compared the weighted average landed value of dumped imports from China with the weighted average net sales realisation of the domestic industry. The Authority calculated the landed value of imports by adding 1% landing charges and the applicable basic customs duty to the CIF import price. In determining the net sales realization of the domestic industry, the Authority excluded rebates, discounts/service charges and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid. It was found that imports from China were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the Indian market. The extent of price undercutting was separately determined for the responding exporters as also for non-cooperative exporters. A high percentage of undercutting was found for the responding exporter.

With regard to change in import volumes, it is clarified that detailed transaction wise information on imports was provided by the petitioner from Secondary Sources, which showed (a) very substantial imports of the product under consideration under Chapter 32 and (b) imports of Rutile grade were reported under classification meant for product under consideration. In view of this position, the Authority referred to the transaction wise import information made available to the DGCI&S and

it was found that imports under Chapter 32 were in fact, far higher than what was claimed by the petitioner. In fact, it was found that the actual volume of exports made by the responding exporters was higher than the volumes claimed by the domestic industry. Authority, therefore, considers it appropriate to revise and correct the import volumes.

As regards allegation of not making available information filed by the domestic industry subsequent to the written submissions, the Authority notes that the domestic industry had provided non confidential version of its submissions, which were placed in the public file. In fact, even Dahua had filed substantial information after the written submissions.

As regards possible double accounting of the import volumes, it is clarified that data from different sources shown in the disclosure statement refers to different periods and imports under different chapter. There can not, therefore, be possibility of double accounting.

The Authority notes that while one of the interested parties had earlier alleged decline in demand, another interested party has now alleged substantial increase in demand and projected the same at the level of 22,500 (unquantified and unverifiable claim). However, the Authority notes that the maximum demand established during the period was 1785 MT whereas the capacity created in the Country is 28100 MT.

## 9.2 Economic Parameters affecting domestic industry :

The injury analysis is related to M/s TTPL, & M/s Kolmac which accounts for a major portion of Indian production and constitutes the domestic industry. Various parameters relating to the performance of the domestic industry are as under: -

### 1. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

Capacity, production, capacity utilisation and sales of the domestic industry shows as under:-

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
Capacity	28100	28100	28100	28100
Production	17511	16891	15774	12892
Capacity utilization	62%	60%	56%	46%
Sales volumes	17286	17011	14921	12265
Sales values (indexed)	100.00	102.37	88.79	70.38

The Authority observes that

- a) Capacity of the domestic industry for the subject goods remained same over the injury period. However, production and capacity utilization significantly declined over the injury period;
- b) Sales volumes have declined significantly. At the same time, import volumes have increased;
- c) The domestic industry may loose further sales, as in spite of reducing prices, the imports are undercutting the prices of the domestic industry.

## 2. Factor affecting domestic prices

(indexed)	1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
Net sales realisation	100.00	104.41	102.29	100.93
Cost of production	100.00	104.39	107.84	118.66
Optimum cost of production				*****

- a) The domestic industry is facing price undercutting. As a direct result, the domestic industry has been forced to reduce the prices. The price undercutting is in the range of 10% to 20%.
- b) The imports are depressing the prices of the domestic industry.
- c) The increase in unit cost of production was primarily due to decline in capacity utilisation and consequently increase in the incidence of overhead costs. However, it was found that the net sales realisation was below optimum cost of production. It is also noted that the decline in capacity utilisation is due to decline in sales volumes as a result of dumped imports in the market. Thus, the increase in unit cost of production is a result of dumped imports from China.
- d) The imports are resulting in price underselling in spite of reduction in the prices by the domestic industry;
- e) The landed value of the imports from the subject country is below the non-injurious price. The imports are thus resulting in price underselling in the market. The price underselling is in the range of 10% to 20%.

With regard to similar level of price undercutting and underselling, it is seen that the non injurious price of the domestic industry is comparatively closer to the net sales realisation. Though non injurious price and net sales realisation are close, injury to the domestic industry is established because the landed price of imports is well below both i.e. the net sales realisation and non injurious price of the domestic industry.

### **3. Employment & wages**

Number of employees has declined over the years. The wages paid by the domestic industry have declined. However, in spite of decline in wages, the domestic industry was suffering adverse profitability.

### **4. Profitability**

In order to analyse the profitability of the domestic industry from production and sales of the subject goods, the Authority examined the unit cost of production, selling price and profit/loss. The relevant details are as under:-

Indexed	1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
Unit Net sales realisation	100.00	104.41	102.29	100.93
Unit cost of production	100.00	104.39	107.84	118.66
Unit profit/loss	100.00	105.55	54.65	(62.25)

Figures in bracket indicate financial loss

It is observed that the Domestic Industry has started incurring financial losses from a situation of profits. The decline in sales volumes directly affected the profitability of the domestic industry.

### **5. Inventories**

In spite of reduction in production, the domestic industry is faced with increasing inventory levels. It would be that the average number of days production is in stock has increased significantly. In fact, at the time of spot verification, attention of the Authority was drawn to the fact that the domestic industry was finding it difficult to stock and maintain the rising inventories. The average level of inventories appeared unprecedented, as would be seen from the table below.

	(Mt)		
1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
1042	1143	1560	3132

### **6. Cash Flow**

Whereas the company was having positive cash flow from production and sale of the subject goods, the cash flow became negative in the investigation period in view of financial losses being suffered by the domestic industry, as is evident from the table below with regard to information relating to cash profits:

Indexed	1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
Cash profits	100.00	101.16	55.97	(18.08)

(Figures in bracket indicates cash loss)

## 7. Productivity

Productivity of the domestic industry, when expressed in terms of production per employee and production per day deteriorated, given the sub-optimal level of production, in spite of reduction in the number of employees.

	1999- 2000	2000- 2001	2001-2002	POI
Production per day	48	46	43	35
Production per employee	21.73	21.58	22.41	19.03

## 8. Growth

Even when the demand for the product has been growing and is positive, the growth of the company has been negative due to dumped imports, as is evident from decline in sales volume, increase in demand and decline in market share of domestic industry in consumption in India.

## 9. Market share

Share of imports from China, other countries, domestic industry and other Indian Producers in consumption in India have been as under:-

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
Share in Demand				
China PR	1%	4%	6%	24%
Other countries	12%	9%	11%	8%
Domestic industry	71%	70%	62%	46%
Other Producers	15%	16%	21%	22%
Total	100%	100%	100%	100%

It is observed from the above that

- a) Share of imports from China in consumption in India increased significantly.
- b) Share of domestic industry in consumption declined.
- c) Share of other Indian Producer increased. However, it was found from the published financial results of the other Indian Producer (M/s. Kilburn Chemicals) that this company was also suffering significant price undercutting and its profitability declined over the period.

## 10. Return on Investments

Significant decline in profits of the domestic industry directly resulted in decline in return on investments. Further, while the

ROI was earlier positive, the same became negative over the injury period, as would be seen from the table below.

Indexed	1999-2000	2000-2001	2001-2002	POI
ROI	100.00	95.73	40.91	(36.07)

### **11. Ability to raise fresh investment**

The domestic industry is finding it difficult to plan fresh investments given that the performance has materially deteriorated.

9.3 Argument has been raised by interested parties that injury to the domestic industry is due to the high incidence of sales tax being borne by the M/s TTPL. It has been further argued that performance of other Indian Producers has not deteriorated. In this regard, the Authority notes that:-

- i) The non-injurious price is determined by the Authority at ex-factory level. Such being the case, any impact of post selling expenses, beyond ex-factory and taxes and duties does not get attributed to dumped imports.
- ii) Performance of other Indian Producers have also deteriorated. M/s Kolmac has since provided costing information as also injury information, which was verified by the Authority. It is seen that the performance of Kolmac also has materially deteriorated. Even though Kilburn Chemicals has not cooperated with the Authority in the present investigations, it appears from the annual report and quarterly reports that this company must also be suffering significant price undercutting and its profitability has also got materially deteriorated.
- iii) The Authority also notes that the argument can be relevant either for injury or causal link. With regard to impact of sales tax on injury to the domestic industry, the Authority notes that Article 3 to the ADA and Annexure II to the Rules with regard to injury to the domestic industry requires an examination of the domestic industry in terms of a number of parameters. Reasons for improvement or decline in these parameters is not required to be examined for the purpose of injury examination. With regard to impact of sales tax from causal link point of view, the Authority notes that (a) the Authority has done complete injury analysis, including assessment of non injurious price, after excluding sales tax, (b) other Indian Producers also have suffered deterioration in profitability. While verified information of Kolmac clearly shows that the performance of the company also significantly deteriorated, annual reports and quarterly results of Kilburn also show significant deterioration. It is also pointed out

that the sales tax being paid by the company was 8% in the POI and not 30% as alleged by some party. 30% was the general rate of sales tax, while the company was granted much lower concessional sales tax rate. As regards ability of the domestic industry to sell quickly with the removal of sales tax, the Authority notes that injury to the domestic industry was much higher than what the Authority has assessed. The ADD was also imposed around the same time. Therefore, it is not relevant that the domestic industry could sell with the imposition of interim ADD and/or removal of sales tax.

#### **10.0 CAUSAL LINK**

1. Volume and value of imports from other countries are either de minimus or the prices are significantly higher, as is seen from the information relating to imports from other countries.
2. Demand for the product is on the increase, as is seen from the table below.

1999-2000	24278
2000-2001	24177
2001-2002	24058
2002-2003	26785

The petitioner has claimed that the imports of the subject goods as reported in the DGCI&S for the POI does not reflect complete imports details. The petitioner has claimed that the imports of subject goods is being reported in classification 3206. In support of this claim the petitioner has submitted details of imports as per secondary sources, which shows substantial imports under 3206. Authority examined detailed transaction wise DGCI&S import information available for 3206 and found that a very significant volume of imports (5735 MT) have been reported under 3206 alone. In fact, exports made by the responding exporters are far higher than the imports reported by the DGCI&S. Possible decline in the demand has, therefore, not contributed to any injury to the domestic industry.

Factors such as changes in pattern of consumption trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.

4. Material injury has been caused to domestic industry from dumped imports, as would be evident from the following:-
  - (a) Landed price of imports from China was lower than the net sales realisation of the domestic industry, forcing the domestic industry to reduce the prices. As a direct consequence, the domestic industry has been forced to

reduced its selling price and consequently a situation of financial losses and cash losses during the period of investigation from a situation of profits and positive cash flow in the preceding years.

- (b) Dumped imports from China resulted in decline in the sales volumes of the domestic industry. As a direct consequence, while the inventories with the domestic industry increased, the production, capacity utilization and productivity deteriorated.
- (c) While the volume of imports and demand of the product increased, the domestic industry registered a negative growth.
- (d) Increase in volume of dumped imports from China resulted in increase in the market share of China. As a direct consequence, the share of domestic industry declined.
- (e) Decline in the selling price of the domestic industry resulted in deteriorating return on investment.
- (f) Performance of the domestic industry has deteriorated and material injury has been caused due to dumped imports.

The above factors establish that injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports.

J. **INDIAN INDUSTRY'S INTEREST:**

- 11.1 The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- 11.2 The Authority recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.
- 11.3 The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

**K. CONCLUSIONS:**

12. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:
  - (I) Titanium Dioxide have been exported to India from China PR below its normal value;
  - (ii) The Indian industry has suffered material injury ;
  - (iv) The injury has been caused cumulatively by the imports from the subject country.
13. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty on all imports of Titanium Dioxide from subject country in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority recommends the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the Petitioner Companies determined for the period of investigation.
14. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties as set out below be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Titanium Dioxide Anatase grade reported under Chapter 28 or any other Chapter of the Customs Tariff Act, originating in or exported from subject countries pending final determination subject to observations made in para above. Since imports of the product have been reported and allowed to be imported under Chapter 32, Anti Dumping Duty shall be applicable in case the goods are reported in other classification also, so long as the imported product is "Titanium Dioxide Anatase grade". The anti dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column (9) table below and the landed value of imports per Mt to be imposed on all imports of subject goods falling under chapter 28 and chapter 32 of the Customs Tariff, originating in or exported from subject country:-

15.

Sl No.	Customs Sub heading	Description	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	28 23 or 32 06	Titanium Dioxide	Anatase	China PR	Any Country	M/s Guangxi Dahua Chemical Factory, China PR	Any exporter	1227.00	Per MT	US \$
2	28 23 or 32 06	Titanium Dioxide	Anatase	China PR	Any Country	M/s Cang Wu Shun Feng Titanium Dioxide Co.Ltd., China PR	M/s ZheJiang Provincial Light & Textile Industry, Haungzhou, China PR	1227.00	Per MT	US \$
3	28 23 or 32 06	Titanium Dioxide	Anatase	Any Country except China PR	China PR	Any producer except M/s. Guangzi Dahua Chemical Factory, China PR M/s. Cang Wu Shun Feng Titanium Dioxide Co. China PR.	Any exporter	1227.00	Per MT	US \$

16. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
17. Subject to the above, the Authority confirms the Preliminary Findings dated 6<sup>th</sup> June, 2003.
18. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act, supra and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose.
19. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority